ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -38 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 21 मई से 27 मई (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

इटली और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक भागीदारी तक बढाने का निर्णय लिया: पीएम मोदी

रोम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली ने व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढाने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे।

मोदी ने बुधवार को यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा कि सुश्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नयी गति और आत्मविश्वास मिला है। उन्होंने कहा कि इसे आगे बढाते हुए दोनों देशों ने अब अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद की कड़ी निंदा करते है और इसे मानवता के लिए गंभीर चुनौती मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले लगभग साढे तीन वर्षों में मुझे कई बार प्रधानमंत्री मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच घनिष्ठ सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्म-विश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हुए विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत और इटली मिलकर उत्पादों का डिजाइन तथा विकास करेंगे और इन्हें दुनिया को उपलब्ध करायेंगे।

मोदी ने कहा, इटली विश्व में डिजाइन और सटीकता के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान पैमाने, प्रतिभा और किफायती नवाचार के पावरहाउस की है। इसलिए हम भारत और इटली में डिजाइन और विकास करेंगे और दुनिया के लिए वितरित करने के सिद्धांत पर आगे बढेंगे।

रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मिलकर काम करने की सहमति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा हमारे रक्षा औद्योगिक रोडमैप से सह-विकास और सह-उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। समुद्री शक्तियों के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, रसद और समुद्री अर्थव्यवस्था पर काम करेंगे।

आतंकवाद पर दोनों देशों के रूख में समानता बताते हुए उन्होंने कहा, भारत और इटली एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। आतंक वित्तपोषण के खिलाफहमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जिम्मेदार लोकतंत्र केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करतीं, बल्कि उसके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने के लिए ठोस कदम भी उठाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया को लेकर भी दोनों देश संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए।

ये नेतृत्व नहीं, सिर्फ नौटंकी है

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तब निशाना साधा जब इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी देते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे सिर पर आर्थिक तूफान मंडरा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में मिठाइयाँ बाँटने में व्यस्त हैं! उन्होंने आगे कहा कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सभी रो रहे हैं - प्रधानमंत्री हँस रहे हैं और रील बना रहे हैं, जबकि भाजपा के लोग तालियाँ बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।

इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली दौरे के दौरान उन्हें मेलोडी टॉफी का पैकेट उपहार में देने का वीडियो साझा किया। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कहती सुनाई दे रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी टॉफी लेकर आए हैं—मेलोडी। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, 卐उपहार के लिए धन्यवाद। बुधवार को अपलोड किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आते हैं और मेलोनी के 'मेलोडी' टॉफी के जिक्र पर हंसते दिखाई देते हैं। मोदी और मेलोनी के नामों के संयोजन के तौर पर 'मेलोडी' हैशटैग पहली बार इटली की प्रधानमंत्री ने 2023 में दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन के दौरान गढ़ा था। इसके बाद दोनों नेताओं की वैश्विक मंचों पर हुई गर्मजोशी भरी मुलाकातों के बीच यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेलोनी ने उस समय भी सोशल मीडिया पर मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए 'मेलोडी' हैशटैग के साथ लिखा था, कॉप-28 में अच्छे दोस्त। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की पांच देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में मंगलवार को रोम पहुंचे।

जशपुर में 94 वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत, 32 को मिल रही नियमित फिजियोथेरेपी सुविधा

सियान गुड़ी बन रही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहारा और सम्मान का केंद्र

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित सियान गुड़ी बुजुर्गों के लिए देखभाल, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रही है।

समाज कल्याण विभाग की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत जिले में अब तक 94 वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 32 बुजुर्गों को नियमित रूप से फिजियोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें शारीरिक समस्याओं से राहत मिल रही है।

हाल ही में जिला अस्पताल की विशेषज्ञ टीम, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिक नर्स और लैब तकनीशियन शामिल थे, इस टीम ने सियान गुड़ी और नशामुक्ति केंद्र के हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्त जांच किया। टीम ने वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह और काउंसिलिंग भी प्रदान की।

सियान गुड़ी में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से वरिष्ठ नागरिक विभिन्न मनोरंजक, सामाजिक और स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दिनभर की गतिविधियों के बाद शाम 6 बजे सभी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों की उपस्थिति में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक शांति का वातावरण बनता है। सियान गुड़ी से लाभान्वित वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र उनके लिए सम्मान, देखभाल और आत्मीयता का स्थान बन गया है।

समाज कल्याण विभाग ने जिले के सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सियान गुड़ी पहुंचकर इस उपयोगी सुविधा का लाभ उठाएं।

आवश्यकता अनुरूप अन्य जिलों में होगा कमिश्नर प्रणाली का विस्तार: विजय शर्मा

रायपुर। राजधानी रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह करने की बात कही है. उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी. छोटे-छोटे विषय विभिन्न विभागों के कारण पेंडिंग हुआ करते थे. अभी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है।

सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ पीआईएल को किया खारिज, कहा- यह सरकार का नीतिगत फैसला

नईदिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. अदालत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं दिखती इसलिए जनहित याचिका को खारिज किया जाता है. याचिका में मांग की गई थी कि आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल न किया जाए।

भारत जिम्मेदार परमाणु शक्ति, 'नो फर्स्ट यूज़' की नीति पर कायम, लेकिन ब्लैकमेल नहीं सहेगा : राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और इन हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति पर दृढता से कायम है लेकिन वह परमाणु ब्लैकमेल को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा।

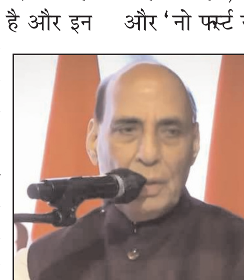

सिंह ने बुधवार को दक्षिण कोरिया के सोल में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की छवि में पहले की तुलना में बहुत बदलाव आया है और अब वह दुनिया में मुद्दों के समाधान देने वाली शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने भाषण के अंश साझा करते हुए कहा, पहले और आज के भारत में स्पष्ट अंतर है। कभी दुनिया भारत को केवल एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखती थी, लेकिन आज दुनिया भारत को समाधान देने वाली शक्ति के रूप में देख रही है। दुनिया भर में विभिन्न टकरावों के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका के बीच उन्होंने कहा , भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और 'नो फर्स्ट यूज़' की नीति पर दृढ़ता से प्रतिबद्ध है लेकिन भारत किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान देश में रक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। भारत की नीति अब 'रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव है ' और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प के साथ भारत स्वदेशी रक्षा निर्माण को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भरता पर बल दिया है तथा सामाजिक न्याय को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हुए बदलावों ने देश का यह विश्वास और मजबूत किया है कि भारत निश्चित रूप से विकसित बन रहा है।

शरद पवार ने जमकर की पीएम मोदी की तारीफ

बोले- वे भारत का मान बढ़ाने में जुटे

मुंबई। एनसीपी (एसपी) नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मंगलवार शाम मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भी हमेशा देश के भविष्य और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

प्रधानमंत्री की तारीफ में क्या बोले शरद पवार?

एनसीपी एसपी प्रमुख ने कहा, राजनीतिक मतभेद भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के आड़े नहीं आने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य शरद पवार

ने पुणे स्थित लक्ष्मणराव गुट्टे ग्रामीण विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित पूर्व पदाधिकारियों के सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में ये बातें कही।

अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए शरद पवार ने बताया कि वर्ष 1958 में 18 साल की उम्र में वे बारामती से पुणे आए थे, क्योंकि उस समय उनके गृह नगर में कॉलेज नहीं था। बाद में वे पुणे शहर यूथ कांग्रेस और फिर महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रमुख बने। पवार ने एक घटना को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात उनके जीवन के यादगार पलों में शामिल है।

शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े प्रसंग किए साझा

उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए किसानों और युवाओं से जुड़े कई सवाल तैयार किए थे, लेकिन नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने वे सब कुछ भूल गए। पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा एक प्रसंग भी सुनाया। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीय प्रधानमंत्री को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। पवार ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सोवियत अधिकारियों से कहा था, मैं 40 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती हूं। यदि उनके सम्मान का आदर नहीं होगा तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। कार्यक्रम के अंत में पवार ने विभिन्न दलों के पुराने सहयोगियों के एक मंच पर आने का स्वागत किया।

बोतल-जर्किन बैन तो निकाला देसी जुगाड़

बाइक में खत्म हुआ पेट्रोल, ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर पहुंचा पंप, वीडियो वायरल

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंपों पर बोतल और जर्किन में पेट्रोल देने पर लगी रोक के बीच गरियाबंद में एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर लोग जहां युवक की समझदारी और नियम पालन की तारीफकर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे 'देसी जुगाड़ का शानदार उदाहरण' भी बता रहे हैं। मामला गरियाबंद-रायपुर रोड स्थित शांति फ़्यूल्स पेट्रोल पंप का है। यहां मंगलवार को अचानक एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पेट्रोल पंप परिसर में पहुंची। ट्रॉली में कोई सामान नहीं, बल्कि एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी। यह नज़ारा देखते ही पेट्रोल पंप कर्मचारी और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ देर तक सभी की नजरें ट्रॉली में रखी बाइक पर ही टिकी रहीं।

जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण युवक अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। पहले उसने आसपास पेट्रोल की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोल पंपों में बोतल और जर्किन में पेट्रोल देने पर प्रतिबंध होने की वजह से उसे कहीं से पेट्रोल नहीं मिल पाया।

इसके बाद युवक ने हार नहीं मानी और गांव

से गरियाबंद की ओर आ रहे एक ट्रैक्टर चालक से मदद मांगी। ट्रैक्टर चालक ने भी इंसानियत दिखाते हुए युवक और उसकी बाइक को ट्रॉली में बैठा लिया। फिर युवक अपनी बाइक को ट्रॉली में लादकर सीधे पेट्रोल पंप पहुंच गया।

पेट्रोल पंप पहुंचने पर जब कर्मचारियों और संचालक ने युवक से पूछा कि वह बाइक को ट्रॉली में रखकर क्यों लाया है, तब युवक ने पूरी कहानी बताई। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। कई लोगों ने युवक की तारीफ करते हुए कहा कि उसने नियम तोड़ने के बजाय उसका पालन किया और सुरक्षित तरीका अपनाया।

शांति फ़्यूल्स के संचालक दीप सिन्हा ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि लोग अब शासन के निर्देशों को गंभीरता से ले रहे हैं और नियमों का पालन भी कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कोई इसे 'ग्रामीण जुगाड़' बता रहा है तो कोई युवक की जागरूकता की तारीफकर रहा है। कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि पेट्रोल नहीं मिला तो पूरी बाइक ही पंप पहुंच गई।

फिलहाल यह वीडियो गरियाबंद समेत आसपास के जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ है और तेजी से वायरल हो रहा है।

मंझोली में मनरेगा का सचः मजदूरों का हक छीना, मशीनों से हुआ काम

कवर्धा। जिले के जनपद पंचायत पंडरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत मंझोली (रवन) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कराए गए निर्माण कार्य को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। स्थल पर लगाए गए नागरिक सूचना पटल में दर्ज जानकारी और जमीनी हकीकत के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। नई बनी संरचना में जगह-जगह दरारें उभर आई हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। नागरिक सूचना पटल के अनुसार यह कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत स्वीकृत है। कार्य का विवरण ग्राम पंचायत मंझोली (रवन) में 96 मीटर लंबाई के निर्माण कार्य के रूप में दर्ज है। प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 3302004015/पीएफ/465238 अंकित है। स्वीकृति अवधि 19.02.2026 कार्य प्रारंभ तिथि 27.02.2026 एवं पूर्णता तिथि 27.03.2026 लिखी गई है। पटल पर प्रदर्शित वित्तीय जानकारी के अनुसार कुल स्वीकृत लागत लगभग 19.59 लाख रुपये बताई गई है। इसमें सामग्री लागत लगभग 17.51 लाख रुपये अंकित है। मजदूरी दिवसों की संख्या 913 दर्ज है तथा प्रति दिवस मजदूरी दर 261 रुपये दर्शाई गई है। तकनीकी सहायक के रूप में सुमित मंडपे एवं कार्यक्रम अधिकारी के रूप में बाबू लाल मेहरा का नाम और मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित है। संबंधित सरपंच और ग्राम पंचायत का उल्लेख भी सूचना पटल पर मौजूद है। लेकिन निर्माण स्थल पर स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हाल ही में पूर्ण बताए जा रहे इस कार्य में कई स्थानों पर दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य में प्रारंभिक चरण में ही दरारें उभरना गंभीर लापरवाही का संकेत माना जाता है। इससे न केवल सरकारी धन के समुचित उपयोग पर सवाल उठता है, बल्कि योजना की विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। सबसे गंभीर आरोप खुदाई कार्य को लेकर सामने आया है। ग्राम पंचायत के पंच फानू सिंह राज ने बताया कि खुदाई का कार्य मजदूरों से नहीं, बल्कि जेसीबी मशीन से कराया गया है। यदि यह आरोप सत्य है, तो यह मनरेगा अधिनियम, 2005 की मूल भावना के प्रतिकूल है। अधिनियम के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मनरेगा एक श्रमप्रधान योजना है, जिसमें मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित है, सिवाय विशेष परिस्थितियों के और वह भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से। मनरेगा में 60:40 का श्रम एवं सामग्री अनुपात अनिवार्य है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। यदि खुदाई जैसे श्रमप्रधान कार्य में मशीनों का उपयोग हुआ है, तो यह न केवल मजदूरों के रोजगार के अधिकार का हनन है, बल्कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में भी आ सकता है। ग्राम स्तर पर लगाए गए नागरिक सूचना पटल का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लेकिन जब पटल पर दर्ज 913 मानव दिवस और मौके पर मशीनों से कार्य कराए जाने के आरोप सामने आते हैं, तो यह पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या कागजों में मजदूरों की हाजिरी दर्ज कर भुगतान दिखाया गया? क्या गुणवत्ता परीक्षण की औपचारिकता पूरी की गई? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रशासन को देना होगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाए। निर्माण की गुणवत्ता का स्वतंत्र परीक्षण हो तथा मशीन उपयोग के आरोपों की सत्यता सामने लाई जाए। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों, तकनीकी अमले और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम एवं वित्तीय नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत मंझोली (रवन) का यह मामला केवल एक निर्माण कार्य की खामियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन पर व्यापक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

जब 96 मीटर के निर्माण में ही दरारें दिखाई देने लगें और श्रमिकों की जगह मशीनों के उपयोग के आरोप लगें, तो जवाबदेही तय करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों के ढ़ेर में दबकर रह जाएगा।

खिलोरा को विधायक दीपेश साहू की विकास सौगात लाखों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

बेमेतरा। सुशासन तिहार के अवसर पर विकासखंड बेमेतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत खिलोरा में आयोजित समाधान शिविर विकास और जनकल्याण का केंद्र बन गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू ने ग्रामवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की महत्वपूर्ण सौगात देते हुए करोड़ों नहीं बल्कि सीधे ग्रामीण जरूरतों से जुड़े ऐसे कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया, जिनसे गांव के लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

लाखों रुपए की लागत से बने सीसी रोड का लोकार्पण

ग्राम खिलोरा में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में विधायक दीपेश साहू ने दो महत्वपूर्ण सीसी रोड निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें भोला के घर से पूरन के घर तक 5.20 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी रोड तथा गयाराम के घर से मौली माता मंदिर तक 5 लाख रुपए की लागत से बने सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन शामिल है।ग्रामीणों ने लंबे समय से इन सड़कों की मांग की थी। बरसात के दिनों में कीचड़ और आवागमन की समस्या से परेशान ग्रामीणों को अब राहत मिलेगी। सड़क निर्माण से गांव के भीतर आवागमन सुगम होने के साथ-साथ मंदिर और आवासीय क्षेत्र तक पहुंच भी आसान होगी। लोकार्पण के दौरान ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

विधायक निधि से बोर खनन और वाटर कूलर की सौगात

ग्रामवासियों की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए विधायक निधि से 2.94 लाख रुपए की लागत से बोर खनन कार्य की सौगात दी गई। इसके साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 लाख रुपए की लागत से वाटर कूलर की सुविधा भी प्रदान की गई।ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या काफी बढ़ जाती थी, लेकिन अब इन सुविधाओं से ग्रामवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक द्वारा किए गए इन कार्यों को ग्रामीणों ने जनहित में महत्वपूर्ण पहल बताया।

मंच निर्माण कार्य का हुआ भूमिपूजन

कार्यक्रम के दौरान विधायक दीपेश साहू ने ग्राम में 5 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित मंच निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन भी किया। यह मंच भविष्य में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन का प्रमुख केंद्र बनेगा। ग्रामीणों ने मंच निर्माण को गांव के विकास और सामाजिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधा बताया।

विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता : विधायक दीपेश साहू

अपने संबोधन में विधायक दीपेश साहू ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास और संवाद का मजबूत माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव-गांव तक विकास पहुंचाने की है, ताकि अंतिम व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा आज जिन कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हुआ है, वे केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि गांव के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं। सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाएं किसी भी गांव के विकास की आधारशिला होती हैं। हमारी सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है कि हर गांव आत्मनिर्भर और सुविधायुक्त बने। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किए जाएंगे तथा ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं संचालित की जाएंगी। विधायक ने ग्रामवासियों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और विकास कार्यों में सहभागी बनने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम में भाजपा संगठन के कई पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सरपंच राधे साहू, उपसरपंच रिखीराम साहू, पंचगण एवं ग्रामवासियों द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में उत्साह और विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

पीएम आवास योजना में लापरवाही पर 700 से अधिक हितग्राहियों से होगी वसूली की तैयारी

बेमेतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों को अपूर्ण छोड़ने वाले 700 से अधिक हितग्राहियों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिला बेमेतरा के जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत ऐसे हितग्राही, जिन्होंने योजना की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद अपने आवास निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। जानकारी के अनुसार, संबंधित हितग्राहियों को पूर्व में नोटिस जारी कर आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनेक मामलों में निर्देशों की अनदेखी की गई। इसके बाद प्रशासन अब दुरुपयोग की गई शासकीय राशि की वसूली के लिए संबंधित तहसीलों से वसूली प्रमाण पत्र जारी कराने की तैयारी में है। इस संबंध में जनपद पंचायत बेरला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीप्ति मंडावी ने हितग्राहियों की पेशी लेते हुए स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग केवल आवास निर्माण कार्य के लिए किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना में लापरवाही एवं राशि के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ मंडावी ने हितग्राहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने नोटिसों की अनदेखी की है और अब तक आवास पूर्ण नहीं किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संबंधित हितग्राहियों से शीघ्र आवास निर्माण पूर्ण करने की अपील भी की है।

10 किलो 539 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बाईक के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार

बेमेतरा। यातायात बेमेतरा प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला एवं यातायात व थाना बेमेतरा पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में संलिप्त पर कार्रवाई तेज करते हुए 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कीमती लगभग 01 लाख 52 हजार रूपये से भी अधिक की 10 किलो 539 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं घटना में प्रयुक्त पुराना इस्तेमाली मोटर सायकल कीमती करीबन 40,000/- रूपये, 02 नग मोबाईल कीमती 16,000/- रूपये, कुल जुमला लगभग 2,08,000/- रूपये को जप्त किया गया हैं।को जप्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा स्टाफ को जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि दो व्यक्ति जो बिना नंबर के मोटर सायकल में सिमगा से बेमेतरा की ओर जा रहे है जो अपने पास रखे बैग में गांजा रखे हुए है कि सूचना पर, उक्त सूचना के संबंध में अधिकारियो को अवगत कराया गया। अधिकारियो के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा सूचना के अधार पर घेराबंदी कर बेरला तिराहा कोबिया के पास, वेल्डिंग शाप के सामने, बेमेतरा सिमगा मार्ग में 02 आरोपियों को मोटर सायकल में अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़ा गया। आरोपी नितेश पटेल पिता रमेश पटेल उम्र 24 वर्ष, भोला ठाकुर ऊर्फ छोटे भाई ठाकुर पिता बालकिशन ठाकुर उम्र 25 वर्ष, दोनों निवासी भडपुरा, थाना भेडाघाट जिला जबलपुर (म.प्र.) के कब्जे से 05 पैकेट में अवैध मादक पदार्थ गांजा 10 किलो 539 ग्राम कीमती करीबन 152,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त पुराना इस्तेमाली मोटर सायकल कीमती करीबन 40,000/- रूपये, 02 नग मोबाईल कीमती 16,000/- रूपये, कुल जुमला लगभग 2,08,000/- रूपये को जप्त किया गया हैं। जिसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा का 01 प्रकरण दर्ज कर 02 आरोपियों के विरूद्ध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई हैं। इस संपूर्ण कार्रवाई में यातायात बेमेतरा प्रभारी रक्षित निरीक्षक प्रवीण खलखो, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक सोनल ग्वाला, सउनि उदलराम टांडेकर, आरक्षक पुरूषोत्तम कुंभकार, शिव सेन, महेश जांगडे, आशीष तिवारी एवं थाना बेमेतरा एवं यातायात स्टाफ की महत्वपूर्ण योगदान रहा।

समाज पर सकारात्मक प्रभावः

आरोपी पर कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

आज राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

जनऔषधि केंद्र रहेंगे खुले, आपात कालीन सेवाओं हेतु हेल्पलाइन जारी

बेमेतरा। राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर देशभर में एकदिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद रखा जाएगा। संगठन के अंतर्गत देशभर के लगभग 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट एवं औषधि वितरक शामिल हैं। यह बंद ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बेमेतरा के केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट संघ द्वारा भी बंद की अग्रिम सूचना का ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया है। संभावित स्थिति को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जिला बेमेतरा ने जिलेवासियों से सतर्कता एवं आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिक तत्काल जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। बंद के दौरान आमजनों को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला चिकित्सालय एवं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों को 24 घंटे खुले रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले के कुछ निजी दवा विक्रेता जैसे अपोलो फार्मेसी एवं धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स इस बंद में शामिल नहीं हैं। आपातकालीन परिस्थिति में नागरिक इन विक्रेताओं से भी दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा आपातकालीन स्थिति में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 9340597097 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं दवाइयों की उपलब्धता संबंधी सहायता हेतु जिला दवा विक्रेता संघ बेमेतरा के अध्यक्ष दिनेश दुबे (94255-23689), सचिव नवीन अग्रवाल (9425513336) तथा कोषाध्यक्ष शरद शर्मा (9893024031) से भी संपर्क किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला दवा विक्रेता संघ से शांतिपूर्ण एवं वैध तरीके से बंद का समर्थन करने की अपील की गई है।

कबीरधाम के जंगलों में 'मुंशी टैक्स' का साम्राज्य तेंदूपत्ता संग्राहकों का शोषण, वन विनाश पर प्रशासन मौन

कवर्धा। जिला जो अपने घने वन क्षेत्रों और आदिवासी बहुल अंचलों के लिए जाना जाता है, इन दिनों तेंदूपत्ता संग्रहण व्यवस्था में व्याप्त कथित अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। जिले के चिल्फी, रेंगाखार, तरेगांव, पंडरिया, बोड़ला और कुकदुर के वन क्षेत्रों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि प्राथमिक लघु वनोपज समितियों के अधीन संचालित तेंदूपत्ता खरीदी केंद्रों में संग्राहकों से खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। जिले में हजारों आदिवासी और वनाश्रित परिवार तेंदूपत्ता संग्रहण पर निर्भर हैं। राज्य स्तर पर 13.76 लाख संग्राहक परिवार इस व्यवस्था से जुड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या कबीरधाम जिले की भी है। आरोप है कि फड़ मुंशी हर 100 गड्डी पर 4 से 5 गड्डी अतिरिक्त वसूल रहे हैं। स्थानीय संग्राहकों के अनुसार यदि यह तथाकथित मुंशी टैक्स नहीं दिया जाए तो पत्ते को घटिया बताकर खरीदी से इनकार कर दिया जाता है। नियमों के अनुसार एक मानक बोरा 1000 गड्डी का होता है, लेकिन भुगतान 950 गड्डी के हिसाब से किया जा रहा है।

इसका सीधा नुकसान संग्राहक परिवारों को उठाना पड़ रहा है। यह व्यवस्था आर्थिक शोषण की श्रेणी में आती है और भारतीय सुधार संहिता की धोखाधड़ी संबंधी धाराओं के तहत जांच योग्य है।

ग्राम सभाओं की अनदेखी

कबीरधाम जिला अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेशा) लागू है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को लघु वनोपज पर स्वामित्व और निगरानी का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद ग्राम सभाओं को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। समितियों को मिलने वाले फंड और आय-व्यय का ब्योरा सार्वजनिक रूप से ग्राम सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। वन धन केंद्र, गोदाम निर्माण और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए लाखों रुपये का प्रावधान होता है, लेकिन इन कार्यों में पारदर्शिता के अभाव की शिकायतें आम हैं। सामाजिक अंकेक्षण की प्र या प्रभावी रूप से लागू नहीं होने से जवाबदेही कमजोर पड़ गई है।

वन अधिकार कानून की भावना पर चोट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए) का उद्देश्य वनवासियों को उनके पारंपरिक अधिकार दिलाना है। तेंदूपत्ता जैसी लघु वनोपज पर उनका वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना इस कानून की मूल भावना है। लेकिन कबीरधाम जिले के वन क्षेत्रों में संग्राहकों के साथ हो रही कथित वसूली इस भावना के विपरीत है। यदि संग्राहकों को उनके संग्रहित पत्तों का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा, तो यह उनके अधिकारों का हनन है।

तेंदू वृक्षों की अंधाधुंध कटाई

जिले के चिल्फी घाटी, रेंगाखार और कुकदुर क्षेत्र में तेंदू वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। नियमानुसार केवल झाड़ीनुमा छोटे पौधों से पत्ते तोड़ने की अनुमति है ताकि वृक्ष जीवित रहें और पुनर्जीवित हो सकें। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अधिक पत्ते और अधिक मजदूरी के लालच में 30-40 फीट ऊंचे वृक्षों को ही काट दिया जा रहा है। यदि यह तथ्य सही पाए जाते हैं तो यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का गंभीर उल्लंघन है। वन विभाग के बीट गार्डों की मौजूदगी में पेड़ों की कटाई होने के आरोप प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े करते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी गति से कटाई जारी रही तो आने वाले वर्षों में तेंदू वृक्षों की संख्या में भारी गिरावट संभव है, जिसका सीधा असर जिले की जैव विविधता और आदिवासी आजीविका पर पड़ेगा।

जिला स्तर पर निगरानी तंत्र पर सवाल

कबीरधाम जिले में संचालित प्राथमिक लघु वनोपज समितियां राज्य स्तरीय लघु वनोपज संघ के अधीन कार्य करती हैं। जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों और प्रबंधकों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शी और नियमसम्मत खरीदी सुनिश्चित करें। समाजसेवी संस्थाओं और जनजातीय समाज प्रमुखों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज कर दोषी फड़ मुंशियों और लापरवाह वनकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही गड्डी प्रणाली समाप्त कर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से किलो के आधार पर खरीदी करने की मांग उठाई गई है, ताकि गड्डी गिनती में होने वाली कथित हेराफेरी रोकी जा सके।

महालेखा परीक्षक से लेखा परीक्षण की मांग

जिले की समितियों के आय-व्यय का स्वतंत्र लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक (सीएजी) से कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय ऑडिट और अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण से ही पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है। कबीरधाम जैसे आदिवासी बहुल जिले में तेंदूपत्ता केवल एक व्यापार नहीं, बल्कि आजीविका का मुख्य आधार है। यदि संग्राहकों का शोषण जारी रहा और जंगलों का क्षरण बढ़ता गया, तो इसका दूरगामी प्रभाव सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों स्तर पर पड़ेगा।

सरकार के लिए यह दोहरी चुनौती

एक ओर संग्राहकों को उनका वैधानिक हक दिलाना और दूसरी ओर तेंदू के जंगलों का संरक्षण करना। जिला प्रशासन की भूमिका इस पूरे प्रकरण में निर्णायक होगी। यदि समय रहते कठोर कार्रवाई, पारदर्शी व्यवस्था और सख्त निगरानी लागू नहीं की गई तो कबीरधाम का वन क्षेत्र आर्थिक शोषण और पर्यावरणीय संकट का केंद्र बन सकता है। अब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही ही तय करेगी कि जिले के संग्राहकों को न्याय मिलता है या यह व्यवस्था यूं ही चलती रहती है।

बालोद में एफसीआई के खिलाफ फूटा राइस मिलर्स का गुस्सा, दूसरे जिलों के चावल स्टाक करने का विरोध

बालोद। जिले में एफसीआई की कार्यप्रणाली को लेकर राइस मिलर्स का आक्रोश अब आंदोलन में बदल गया है। एफसीआई गोदामों में दूसरे जिलों के चावल को स्टैक अलॉटमेंट दिए जाने के विरोध में बालोद जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आंदोलन के तहत एफसीआई गोदामों में काम बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही मिलर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो कांकेर और बस्तर से आने वाले चावल के लॉट भी रोक दिए जाएंगे। झलमला-धमतरी मुख्य मार्ग स्थित ग्राम जगतरा के एफसीआई कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में राइस मिलर्स धरने पर बैठे हैं। भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद आंदोलनकारियों का उत्साह कम नहीं दिखा। प्रदर्शन स्थल पर जिलेभर के मिलर्स एकजुट होकर एफसीआई प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए।

राइस मिलर्स का आरोप है कि बालोद जिले का खुद का चावल अभी गोदामों में पर्याप्त मात्रा में जमा होना बाकी है, इसके बावजूद एफसीआई द्वारा कांकेर, धमतरी और बस्तर जिले के मिलर्स को प्राथमिकता देकर यहां स्टैक अलॉटमेंट दिया जा रहा है। इससे स्थानीय मिलर्स को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मांगों पर तत्काल निर्णय लिया जाए : विजय मिश्रा

जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय मिश्रा ने कहा कि बालोद जिले के गोदामों में वर्षों से दूसरे जिलों का चावल जमा किया जा रहा है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। कई बार एफसीआई के डीएम और जीएम से चर्चा कर स्थानीय मिलर्स को प्राथमिकता देने की मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि चिटौद गोदाम का आधा हिस्सा धमतरी जिले को दिया गया है, जबकि वहां पहले से गोदाम उपलब्ध हैं और रेल हेड भी शुरू होने वाला है। ऐसे में बालोद जिले के गोदामों में बाहरी जिलों का चावल रखना पूरी तरह अनुचित है। विजय मिश्रा ने कहा कि लगभग 130 मिलर्स और कर्मचारी आंदोलन में शामिल हैं। प्रशासन से अपील है कि स्थिति को गंभीर होने से पहले मांगों पर तत्काल निर्णय लिया जाए। उन्होंने साफकहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

ठोस निर्णय नहीं लेने से मिलर्स में बढ़ती जा रही है नाराजगी

जिला राइस मिल एसोसिएशन के संरक्षक मोहन भाई पटेल ने कहा कि खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए अरवा और उसना राइस मिलर्स का जितना डीओ कटा है, उसके अनुपात में चावल जमा करने के लिए जगतरा, कोटेरा और चिटौद डिपो में पर्याप्त जगह नहीं बची है। इसके बावजूद अन्य जिलों के चावल को यहां स्टोर किया जा रहा है, जिससे स्थानीय मिलर्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच भी मिलर्स जिस एकजुटता और उत्साह के साथ धरने पर बैठे हैं, उससे साफहै कि इस बार आंदोलन निर्णायक रूप ले सकता है। प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन के सदस्य प्रियंक वैष्णव ने एफसीआई प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जगतरा में बालोद जिले को साढ़े 10 हजार लॉट की टैगिंग दी गई है, जबकि पिछले वर्षों में जिले से 7 हजार लॉट से अधिक का मूवमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी बड़ी टैगिंग किस आधार पर दी गई, इसका जवाब एफसीआई को देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एफसीआई अधिकारियों द्वारा बार-बार आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे स्थानीय मिलर्स में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।

राज्यपाल रमेन डेका ने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा

- **महिला आजीविका संवर्धन, युवाओं के हुनर को तराश कर आत्मनिर्भर बनाने, सड़क सुरक्षा पर जोर देने, टीबी उन्मूलन पर विशेष कार्ययोजन बनाने, जल संचयन पर कार्य करने सहित टीबी उन्मूलन पर कार्ययोजना बनाने कहा**

बेमेतरा। राज्यपाल रमेन डेका ने बेमेतरा में शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव या प्रशासनिक जटिलताओं के कारण लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस अवसर पर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई एवं एसएसपी रामकृष्ण साहू सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे। राज्यपाल ने निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। सर्वे और चयन की प्रक्रिया को इतना सुदृढ़ बनाया जाए कि वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिले। राज्यपाल डेका ने कहा कि कई बार ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में लोगों को योजनाओं की सही जानकारी नहीं होती। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। जिससे ग्रामीण जनों को योजनाओ का लाभ मिल सकें। बैठक के समापन पर राज्यपाल ने कहा कि सभी अधिकारी शिद्दत के साथ मानवीय संवेदना को अपने जीवन में विशेष जगह देवें। उन्होंने कहा कि समाज में वंचित और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन के साथ समय बिताए और उनका ख्याल रखें। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा अध्ययन में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जीवन में सकारात्मक सोच को जगह देवें। जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए हितग्राहियों को लाभांवित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं में केवल आंकड़े पूरा करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि आम जन के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने और सेवा भाव को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। राज्यपाल रमेन डेका द्वारा दिए गए ये निर्देश राज्य के समग्र विकास, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके इस विज़न को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने निर्देशित किया। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रणनीतिक बनाने कहा। स्वयं सहायता समूह का सुदृढ़ीकरण करने कहा। बिहान' या स्थानीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को जोड़कर उन्हें बैंक लिंकेज और कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा कर आर्थिक स्वावलंबन बनाने कहा गया। राज्यपाल रमेन डेका ने पारंपरिक कार्यों से हटकर महिलाओं / युवाओ का कौशल उन्नयन करने कहा। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण पर जोर दिया। युवाओं के हुनर को तराश कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने कहा गया। उन्होंने युवाओं को रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाने पर ध्यान देना कहा।

स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा-राज्यपाल रमेन डेका ने युवाओं को 'मुद्रा योजना' या राज्य की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आसानी से लोन दिलाने और उन्हें मेंटरशिप प्रदान करने निर्देशित किया।कौशल प्रशिक्षण के तुरंत बाद युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए जिला स्तर पर 'रोजगार मेलों' का नियमित आयोजनकरने भी कहा।

सड़क सुरक्षा पर ज़ोर-सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और कीमती जानों को बचाने के लिए एक 'थ्री-ई' जिला प्रशासन को ठोस पहल करने निर्देशित किया। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। जिन जगहों पर बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं, वहां सड़कों का सुधार, साइनबोर्ड लगाना और स्पीड ब्रेकर दुरुस्त करने कहा गया। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना के तुरंत बाद का समय) में मदद करने के लिए 'गुड सेमरीटन' (नेक फरिश्ते) नीति का प्रचार करने निर्देशित किया।

टीबी उन्मूलन पर विशेष कार्ययोजना बनाएं-भारत सरकार के 2025-2026 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माइक्रो-प्लानिंग की जरूरत बताया। ग्रामीण, आदिवासी और मलिन बस्तियों में घर-घर जाकर टीबी के लक्षणों वाले मरीजों की पहचान करने कहा गया। टीबी मरीजों को इलाज साथ ही, समाज के संपन्न लोगों और अधिकारियों को 'निक्षय मित्र' बनाकर मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने कहा गया, ताकि उन्हें अतिरिक्त पोषण मिल सके। जल संचयन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाने निर्देशित किया। बढ़ती गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए इन पारंपरिक और आधुनिक उपायों पर प्रभावी काम करना समय की मांग बताया। राज्यपाल रमेन डेका डबरी निर्माण, छोटे आकार के तालाब बनाकर जल संचयन करने निर्देशित किया। सभी शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग बनाने कहा गया।

कागजों में खरीदी, गोदाम खाली : किसानों की कमाई पर सिस्टम की सेंध

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया जा रहा है। लेकिन कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के मध्यप्रदेश सीमा से लगे उपार्जन केंद्रों से सामने आए आंकड़े इस दावे की नींव हिला रहे हैं। हजारों क्विंटल धान की दर्ज कमी ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मूल्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उसरवाही उपार्जन केंद्र में कुल 1,01,968.80 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज है, जबकि 2,775.44 क्विंटल की कमी सामने आई है। रेंगाखार कला में 66,306.00 क्विंटल खरीदी के मुकाबले 639.63 क्विंटल कम पाया गया है। बम्हनी केंद्र में 55,220.40 क्विंटल खरीदी के विरुद्ध 2,508.52 क्विंटल की कमी दर्ज है। झलमला में 42,903.60 क्विंटल खरीदी के सामने 363.33 क्विंटल की कमी बताई गई है। यह कुल मिलाकर हजारों क्विंटल धान का अंतर है, जिसे किसी भी सूरत में सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नहीं माना जा सकता। ऑनलाइन पोर्टल पर स्टॉक में कमी दर्ज होना और भौतिक सत्यापन में केंद्रों पर धान का अभाव मिलना स्थिति को और गंभीर बनाता है। यदि खरीदी वास्तविक थी तो स्टॉक की सुरक्षा और भंडारण में भारी लापरवाही हुई है। यदि स्टॉक कागजों में बढ़ाया गया है तो यह सीधे-सीधे बोगस खरीदी का मामला बनता है। दोनों ही स्थितियों में सार्वजनिक धन और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि संबंधित उपार्जन केंद्रों का अंतिम भौतिक मिलान एवं लेखा परीक्षण अभी शेष बताया जा रहा है। सीमावर्ती भौगोलिक स्थिति इस मामले को और संवेदनशील बनाती है। मध्यप्रदेश से सटे इन क्षेत्रों में ऊंचे समर्थन मूल्य का लाभ उठाने की संभावनाएं लंबे समय से चर्चा में रही हैं। ऐसे में बाहरी धान की एंट्री, कागजी खरीदी और परिवहन श्रृंखला में गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि इस तरह का संगठित खेल हुआ है तो यह केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में गहरी पैठ का संकेत है। जिम्मेदारी तय करने की दिशा में सबसे पहले उपार्जन केंद्र प्रभारियों की भूमिका की जांच आवश्यक है। खरीदी, तौल, भंडारण और परिवहन की प्रविष्टियां उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती हैं। सहकारी समिति प्रबंधक, गोदाम प्रभारी और परिवहन एजेंसियां भी इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। जिला स्तर पर खाद्य विभाग, विपणन संघ और वेयरहाउसिंग अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा जरूरी है। यदि नियमित निरीक्षण और स्टॉक मिलान समय पर और पारदर्शी तरीके से हुए होते तो इतनी बड़ी कमी सामने आने से पहले ही रोकथाम संभव थी। प्रशासनिक जवाबदेही से बचने का कोई अवसर नहीं है। हजारों क्विंटल धान की कमी केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन का मामला है। यदि भुगतान जारी हुआ है तो बैंकिंग रिकॉर्ड, परिवहन चालान और भंडारण रजिस्टर की क्रॉस-चेकिंग अनिवार्य है। दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर निलंबन, सेवा से पृथक्करण और रिकवरी की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर भरोसे और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन उसी व्यवस्था में सेंध लगाकर निजी लाभ कमाना अन्नदाताओं के साथ सीधा विश्वासघात है। यह मामला केवल कबीरधाम तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और समर्थन मूल्य व्यवस्था की विश्वसनीयता राष्ट्रीय महत्व का विषय है। अब समय है कि जिला प्रशासन उच्चस्तरीय, समयबद्ध और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। सभी संबंधित केंद्रों का पुनः भौतिक सत्यापन, डिजिटल डेटा ऑडिट, सीसीटीवी रिकॉर्ड की समीक्षा और परिवहन श्रृंखला का विस्तृत परीक्षण किया जाए। पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई ही इस पूरे प्रकरण में जनता का विश्वास बहाल कर सकती है।

मेमू ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 08 कोच से किए 12 कोच

दल्लीराजहरा। रायपुर-राजहरा- ताड़ोकी-रायपुर 68764/ 68765 मेमू ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 08 कोच से 12 कोच किए गए हैं। इस क्षेत्र के यातायात निरीक्षक एवं वाणिज्य निरीक्षकों को यात्रियों से फीडबैक लेने एवं समीक्षा के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा आगे के संभावित निर्णय लिए जाएंगे। इस ट्रेन में 08 कोच के स्थान पर 12 कोच होने से यात्रियों को फायदा मिलेगा एवं यात्रियों की प्राथमिक मांग की पूर्ति होगी। रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर 68764/68765 मेमू ट्रेन का कम लंबाई वाले प्लेटफार्म वाले स्टेशन रिसामा, गुंडरदेही, लाटाबोर, कुसुमकसा स्टेशनों पर रायपुर ताड़ोकी रायपुर ट्रेन का ठहराव 2 मिनट अतिरिक्त बढ़ाया गया है। पहले यह गाड़ी इन स्टेशनों पर 1 मिनट के लिए रुकती थी 2 मिनट अतिरिक्त बढ़ाए जाने पर यह गाड़ियां 3 मिनट के लिए उक्त स्टेशनों पर रुकेगी। यह व्यवस्था 18 मई 2026 से लागू कर दी गई है। गाड़ी संख्या 68764 रायपुर ताड़ोकी मेमू पैसेंजर ट्रेन 18:00 बजे रवाना होकर मरौदा 19.15 बजे पहुंच कर 19:25 बजे रवाना होगी। रिसामा स्टेशन पर 19.38 बजे पहुंच कर 19.41 बजे रवाना होगी, गुंडरदेही स्टेशन पर 19.52 बजे पहुंच कर 19.55 बजे रवाना होगी लाटाबोर स्टेशन पर 20.11 बजे पहुंच कर 20.14 बजे रवाना होगी, कुसुमकसा स्टेशन पर 20.42 बजे पहुंच कर 20.45 बजे रवाना होगी यह गाड़ी तड़ोकी स्टेशन पर 22.45 बजे पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 68765 ताड़ोकी-रायपुर मेमू पैसेंजर 10:25 बजे ताड़ोकी से रवाना होकर कुसुमकसा स्टेशन पर 11.51बजे पहुंच कर 11:59 बजे रवाना होगी।

लाटाबोर स्टेशन पर 12. 27 बजे पहुंच कर 12:30 बजे रवाना होगी। गुंडरदेही स्टेशन पर 12.49 बजे पहुंच कर 12:52 बजे रवानाहोगी। रिसामा स्टेशन पर 13:00 पहुंचकर 13:03 बजे रवाना होगी। मरौदा स्टेशन पर 13:30 बजे पहुंच कर 13:40 बजे रवाना होगी। रायपुर 15.40 बजे पहुंचेगी।

आबकारी एक्ट के 01 प्रकरण में 01 आरोपी के कब्जे से 49 पौवा शराब जप्त

बेमेतरा। बेमेतरा पुलिस द्वारा अवैध शराब, गांजा, नशीली पदार्थो, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, बाउंड ओवर, गुंडा बदमाशों, फरार स्थायी वारंटियो, सामाजिक सौहार्द बिगाडने वालों, यातायात नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा माईनर एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना नांदघाट पुलिस टीम को जरिये मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अपने पास में एक सफेद रंग के थैला में अवैध रूप से धन लाभ अर्जित करने अवैध रूप से शराब बिक्री करने तरपोंगी तिराहा ग्राम नांदघाट में खडा हैं कि सूचना के अधार पर थाना नांदघाट एवं साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा रेड कार्यवाही कर तरपोंगी तिराहा ग्राम नांदघाट में एक व्यक्ति को बिक्री हेतु रखे अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। जिसमें थाना नांदघाट में 01 प्रकरण में 01 आरोपी तोषण कुमार मिरी पिता मनाराम मिरी उम्र 29 वर्ष, निवासी धोबघट्टी, थाना नांदघाट जिला बेमेतरा के कब्जे से 37 पौवा अंग्रेजी शराब एवं 12 पौवा देशी मसाला शराब, कुल 49 पौवा अंग्रेजी/देशी मसाला शराब (8,820द्वद्य) कुल जुमला कीमती 5,640/- रूपये को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई हैं। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नांदघाट निरीक्षक लेखराम ठाकुर, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक मयंक मिश्रा, प्रधान आरक्षक खुलेश्वर गायकवाड, साइबर सेल प्रधान आरक्षक योगेश यादव, आरक्षक संजय पाटिल, मुकेश माहिरे, थाना नांदघाट से आरक्षक संजय साहू, प्रताप सिंह यादव, मिथुन चंद्रवंशी, अजय गोयल अकाश सिंह सहित थाना नांदघाट/साइबर सेल के समस्त पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

पेट्रोल डीजल के लिए शहर में मारामारी, होने लगे मारपीट

बेमेतरा। ज़िला मुख्यालय सहित जिले के कई डीजल पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल नहीं होने के कारण इन दोनों लोगों को डीजल पंप डीजल पेट्रोल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जहां पर मिलने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है जिसमें वहां पर दो पहिया वाहन से लेकर सभी तरह के वाहनों की लाइन लग जाती है। वर्तमान में एक तरफजहां खेती किसानी का सीजन शुरू हो रहा है वहीं दूसरे तरफ शादी ब्याह का भी अभी सीजन चल रहा है।

इसके अलावा हर लोगों के पास दोपहिया से लेकर चार पहिया वाहन से लेकर कई पहिया का वाहन है। जिसका उपयोग लोगों के द्वारा किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत सख्त आवश्यकता रहती है। ऐसी स्थिति में डीजल पेट्रोल की कमी होने से लोगों में एक तरफ जहां भंडारण करने की होड़ लग गई है। इसके चलते लोग डीजल पेट्रोल पंप में लाइन परा पर भी डीजल पेट्रोल मिलने की खबर मिलते ही भीड़ पहुंच जाता है। हालात यहां तक पहुंच गई है कि कुछ पेट्रोल पंप जहां पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध रहते हैं वहां पर वाद विवाद से लेकर के मारामारी मारपीट तक के हो रही है। बेमेतरा जिला के सभी प्रमुख स्थान एवं नगर कस्बा एवं सड़क किनारे बहुत सारे पेट्रोल पंप डीजल पंप है। लेकिन इन दोनों ईरान से अमेरिका और इजरायल युद्ध होने के परिणाम स्वरूप पेट्रोल डीजल की आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है जिसके कारण शहर एवं ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल डीजल की कमी से लोगों को परेशानी हो रही है। अभी जिला मुख्यालय में प्रतिदिन किसी न किसी अधिकांश पेट्रोल डीजल पंप में डीजल पेट्रोल नहीं होने की शिकायती मिल रही है वहीं जहां पर पेट्रोल डीजल मिलाने की जानकारी होती है वहां पर लोग डीजल पेट्रोल लेने के लिए लंबी-लंबी लगा रहे हैं यह स्थिति तब तक कश रहता है। जब तक के पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल समाप्त नहीं हो जाता।

कई लोग जब पता चलता है कि रात 2:00 बजे पेट्रोल डीजल आया है तो लोग 5:00 बजे वहां पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इस संबंध में यह भी जानकारी मिली है कि जिला मुख्यालय की हालत बहुत खराब है। यहां शहर के अंदर रायपुर रोड में बीजाभाठ रोड में इधर बालसमंद रोड में नवगढ़ रोड में खमरिया रोड कवर्धा रोड में जितने भी डीजल पेट्रोल पंप है उसमें कई डीजल पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल पंप की कमी आए दिन होने लगा है इस लिए जिस किसी भी पेट्रोल पंप में डीजल पेट्रोल मिलने की खबर लोगों को होता है। वहां पर लोग डीजल पेट्रोल लेने के लिए एकत्र हो जाते हैं जिससे वहां पर मेला का माहौल बन जाता है।

लोग स्टाक करने में लगे डीजल पेट्रोल को

डीजल पेट्रोल की कमी की की चर्चा के चलते इन दिनों कतिपय लोगों के द्वारा डीजल पेट्रोल को खरीद कर भविष्य के लिए स्टाक में रखना शुरू कर दिए हैं।

इस संबंध में लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल पंप अभी यहां किल्लत होने लगा है, ऐसा लगता है कि भविष्य में कहीं डीजल पेट्रोल पंप 6 दिन 8 दिन के लिए मिलना बंद हो जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने काम को सुचारू से संचालित करने के लिए डीजल पेट्रोल को खरीद कर भारी मात्रा में स्टाक करने भी लग गए हैं। इसके कारण भीड़ जो है कम नहीं हो रही है, बल्कि जिस पंप में पेट्रोल डीजल मिलने की जानकारी होते ही वहां पर भीड़ उमड़ पड़ती है।

15 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह उत्साह और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न

दल्लीराजहरा। दल्ली मॉडर्न आर्ट क्लब (डी मेक) द्वारा आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप 2026 का भव्य समापन समारोह उत्साह और रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा, कला और आत्मविश्वास ने उपस्थित सैकड़ों लोगों का मन मोह लिया। समापन समारोह में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विभिन्न स्कूलों के उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को ट्रॉफी एवं सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। संस्था द्वारा सम्मानित विद्यार्थियों में सुमन वर्मा (98% 10वीं, डीएवी स्कूल), शुभोश्री आचार्जी (98% 10वीं, डीएवी स्कूल), श्रेयांश गुप्ता (95.6% 10वीं, निर्मला स्कूल), मानस अग्रवाल (93.2% 12वीं, डीएवी स्कूल), समृद्धि कसार (91.2% 12वीं, निर्मला स्कूल), पायल वर्मा (91% 10वीं, आत्मानंद स्कूल), अदिति पासवान (86.2% 12वींआत्मानंद स्कूल), यमन कुमार देवांगन (83% 10वीं, लिटिल बर्ड अकादमी) को 2026 टॉपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। संस्था ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये बच्चे आगे चलकर दल्ली राजहरा, जिला और राज्य का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में समर कैंप के प्रशिक्षक सारिका, भूमिका, लीसा, प्रिया, सिरी, मिलन, महेश एवं हेमंत की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया। लगभग 6 वर्षों से डी-मेक संस्था बच्चों को समर कैंप के माध्यम से वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, मेहंदी, रंगोली, स्पोकन इंग्लिश, कैलिग्राफी, कर्सिव राइटिंग, माइंड गेम्स जैसी रचनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया से निकालकर उनकी रचनात्मक, बौद्धिक और कलात्मक प्रतिभा को निखारना है, ताकि बच्चे खेलकूद और पढ़ाई के साथ-साथ नई-नई क्रिएटिव चीजें सीख सकें। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। साथ ही हाल ही में दल्ली राजहरा में पाइपलाइन कार्य के दौरान मृत हुए तीन मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की गई। इसके पश्चात राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। नन्हे बच्चों ने मंच संचालन से लेकर डांस, ग्रुप सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, कृष्णा स्टोरी आधारित प्रस्तुतियों और कला प्रदर्शनी के माध्यम से अपने आत्मविश्वास और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। 3 साल से छोटे बच्चों तक ने मंच पर बेहतरीन प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू, मंडल अध्यक्ष रामेश्वर साहू, जयदीप गुप्ता, राजकुमार साहू, एम.एस. श्रीजीत एवं आदित्य उपस्थित रहे। संस्था के डायरेक्टर विजय बोरकर ने कहा कि दल्ली राजहरा जैसे शहर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।

रेलवे इंस्टिट्यूट में 1 से 30 मई तक समर कैंप का आयोजन

दल्लीराजहरा। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर कर खेल की ओर मोड़ने के उददेश्य से रेलवे इंस्टिट्यूट दल्ली राजहरा में 1 से 30 मई तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है इसमें 340 बच्चे निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं। आयोजकों के अनुसार दिन-प्रतिदिन बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कैंप के मुख्य कोच और रेलवे इंस्टिट्यूट के सहायक सचिव एडवर्ड स्टीफन ने बताया कि इस समर कैंप का उददेश्य बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करने के साथ-साथ खेलों के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों में बच्चे पढ़ाई से तो दूर होते ही हैं, साथ ही समय का अधिकतर हिस्सा मोबाइल, टीवी और नींद में बर्बाद कर देते हैं। संसाधन और जगह की कमी के कारण बच्चे खेलों से दूर होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए रेलवे इंस्टिट्यूट ने निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे बच्चों को बुलाकर एक घंटे तक फिजिकल एक्सरसाइज और दौड़ कराई जाती है। इसके बाद बच्चे अपनी रुचि के अनुसार फुटबॉल, कबड्डी और अन्य फिजिकल गेम्स का अभ्यास करते हैं। सभी खेलों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षक निशुल्क सेवा दे रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू और वार्ड 26 की पार्षद टी. ज्योति ने कैंप पहुंचकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। आयोजक समिति ने दोनों अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर समाजसेवी तरुण चंद्रा और सुजीत झा भी मौजूद रहे, जिनका भी स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि तोरण लाल साहू ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चार सालों से रेलवे इंस्टिट्यूट बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेल का प्रशिक्षण दे रहा है। यह प्रयास बच्चों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उनके शारीरिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने रेलवे इंस्टिट्यूट और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि पहले स्कूलों में जबरन खेल सिखाए जाते थे, लेकिन अब बच्चे बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के खेल सीख रहे हैं। पार्षद और कोचों के अनुरोध पर उन्होंने ग्राउंड को बड़ा करने के लिए अधिकारियों से बात करने की बात भी कही, ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। पार्षद टी.ज्योति ने कहा कि यह कैंप रेलवे बीआरएम के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है और सभी सुविधाएं रेलवे की ओर से निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने प्रशिक्षकों और आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह एक बड़ी पहल है। कैंप में आए सभी 340 बच्चों के लिए नाश्ते की व्यवस्था समाजसेवी तरुण चंद्रा ने की। उन्होंने बच्चों को बिस्कुट, केला और फल वितरित किए। आयोजकों ने बताया कि संस्थान की ओर से बच्चों को नियमित रूप से गुड़-चना, दूध और बिस्कुट भी दिए जाते हैं। किसी बच्चे का जन्मदिन होने पर परिवार के सहयोग से यहां उसका उत्सव भी मनाया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हर सप्ताह अनुशासित और लगनशील एक लड़के और एक लड़की को टोपी देकर सम्मानित किया जाता है।

संपादकीय

सोने पर सख्ती, क्या आर्थिक दबाव से निपटने की शुरुआत है यह बड़ा संकेत

भारत बहुमूल्य धातुओं का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कच्चे तेल के बाद सोने का देश के आयात में दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसकी बढ़ती मांग और आयात से विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर देश की जनता से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन कम खर्च करने और सोना न खरीदने को कहा है।सरकार के इस कदम का एक पहलू यह भी है कि इससे सोने-चांदी की कालाबाजारी और तस्करी बढ़ने की आशंका है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे संकट का फिलहाल कोई स्थायी हल नजर नहीं आने के मद्देनजर भारत में इसके प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर अमल शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री की ओर से हाल में जनता से किए गए आग्रह के बाद सोने-चांदी पर आयात शुल्क छह फीसद से बढ़ाकर पंद्रह फीसद कर देने की घोषणा से की गई। इसके बाद इन कीमती धातुओं के दाम में बुधवार को भारी उछाल आया। सरकार का कहना है कि संकट के समय गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहे दबाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।दरअसल, भारत बहुमूल्य धातुओं का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कच्चे तेल के बाद सोने का देश के आयात में दूसरा बड़ा हिस्सा है। इसकी बढ़ती मांग और आयात से विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि, आभूषण कारोबारी सरकार के इस कदम से निराश हैं, लेकिन यह भी सच है कि समय रहते समुचित उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में जो जटिल परिस्थितियां पैदा होंगी, उनका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर देश की जनता से विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, भोजन पकाने के तेल के इस्तेमाल में कमी लाने और सोने की खरीद एवं विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने का आह्वान किया था। संदेश स्पष्ट था कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों की ओर बढ़ना होगा।इसमें दोराय नहीं है कि किसी भी बड़े संकट से निपटने के लिए आम नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है। जन भागीदारी के बिना न तो कोई योजना सफल हो पाती है और न ही संकट के दौरान आवश्यक उपायों का व्यापक स्तर पर सार्थक परिणाम सामने आता है। सोने-चांदी की खरीद नागरिकों की मूलभूत जरूरतों से परे है और इसे कुछ समय के लिए सीमित कर देने से अगर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कुछ कम हो जाए, तो यह एक सार्थक पहल साबित हो सकती है।सरकार के इस कदम का एक पहलू यह भी है कि इससे सोने-चांदी की कालाबाजारी और तस्करी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। जमीनी और तटीय घुसपैठ मार्गों, संगठित तंत्र और वितरण केंद्रों के रूप में काम करने वाले कारोबारियों पर नियमित नजर रखनी होगी।

ट्रंप और जिनपिंग की दोस्ती ने बदल डाले वैश्विक राजनीतिक समीकरण, क्वाड का भविष्य अधर में

(नीरज कुमार दुबे)

ट्रंप की चीन यात्रा ने यह भी साफ कर दिया कि चीन को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है। वहीं बीजिंग ने ट्रंप की इस यात्रा को केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अपनी तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति के प्रदर्शन में बदल दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा बदलती विश्व व्यवस्था का ऐसा प्रतीक बनकर सामने आई जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की लंबी बैठकों, व्यापारिक समझौतों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी सहयोग पर चर्चा तथा अमेरिकी उद्योगपतियों की भारी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि तमाम टकरावों और आरोपों के बावजूद अमेरिका और चीन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसी के साथ यह सवाल भी तेज हो गया है कि क्या इस यात्रा ने क्वॉड जैसे रणनीतिक समूहों के भविष्य पर भी अनिश्चितता पैदा कर दी है?

दिलचस्प बात यह है कि पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, तब ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमेरिका भारत को चीन और रूस के हाथों खो रहा है। यही नहीं, मोदी की चीन और रूस के नेताओं के साथ तस्वीरों को वाशिंगटन में रणनीतिक असहजता के रूप में देखा गया था। लेकिन अब वही ट्रंप खुद चीन की धरती पर शी जिनपिंग के साथ बैठकों में व्यस्त रहे। उनके साथ अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति और तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी मौजूद रहे। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि यदि भारत का चीन से संवाद अमेरिका के लिए भारत को खो देना था, तो फिर ट्रंप की अपनी चीन यात्रा को क्या कहा जाए? क्या यह अमेरिकी यथार्थवाद है, आर्थिक मजबूरी है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की नई स्वीकारोक्ति है?

ट्रंप की इस यात्रा ने यह भी साफ कर दिया कि चीन को अलग थलग करने की अमेरिकी रणनीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है। वहीं बीजिंग ने ट्रंप की इस यात्रा को केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अपनी तकनीकी, आर्थिक और सामरिक शक्ति के प्रदर्शन में बदल दिया। शहर की सड़कों पर चालक रहित विद्युत वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां, मानवरूपी रोबोट और डिजिटल विज्ञापन चीन की नई ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। चीन दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि अब वह केवल सस्ती वस्तुएं बनाने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाली शक्ति बन चुका है।

देखा जाये तो ट्रंप की यात्रा ऐसे समय हुई जब अमेरिका ईरान युद्ध के कारण कई मोर्चों पर दबाव में है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने ईरान संकट का उपयोग अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के बीच चीन ने ऊर्जा आपूर्ति और हथियारों के जरिये अपनी भूमिका बढ़ाई, जबकि अमेरिका युद्ध और आर्थिक दबावों में उलझा रहा। यही कारण है कि ट्रंप को अंततः बीजिंग पहुंचकर शी जिनपिंग से संवाद करना पड़ा।

बीजिंग में हुई बातचीत के दौरान ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि यदि ताइवान के मुद्दे को ठीक ढंग से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। यह बयान केवल चेतावनी नहीं था बल्कि बदलते शक्ति संतुलन का संकेत भी था। चीन अब अमेरिका से बराबरी की भाषा में बात कर रहा है।

ट्रंप की प्राथमिकता हालांकि व्यापार और निवेश रही। उनके साथ एलन मस्क, जेन्सन हुआंग और अन्य अमेरिकी उद्योगपति भी पहुंचे। यह इस बात का संकेत था कि अमेरिकी उद्योग जगत चीन से दूरी नहीं चाहता। दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और विशाल तकनीकी बाजार से अलग होना अमेरिका के लिए आसान नहीं है।

व्हाइट हाउस की ओर से जारी आधिकारिक बयान ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई संवेदनशील मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए। बयान के अनुसार ट्रंप और शी जिनपिंग ने अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में बाजार पहुंच बढ़ाने, चीन के निवेश को अमेरिका में प्रोत्साहित करने और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न होने देने पर भी सहमति जताई। चीन ने जलडमरूमध्य के सैन्यीकरण का विरोध दोहराया, जबकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने पर भी साझा रुख सामने आया। यह बयान इस बात का संकेत है कि तीखी प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद अमेरिका और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर टकराव के बजाय नियंत्रित सहयोग की राह भी तलाश रहे हैं।

यही वह बिंदु है जहां क्वॉड का भविष्य भी सवालों में घिरता दिखाई देता है। क्वॉड को लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाले समूह के रूप में देखा जाता रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की यह साझेदारी चीन को लेकर साझा रणनीतिक चिंता पर आधारित मानी जाती है। लेकिन यदि अमेरिका का राष्ट्रपति खुद चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने, व्यापार बढ़ाने और तकनीकी सहयोग तलाशने बीजिंग पहुंचता है, तो फिर क्वॉड की वास्तविक दिशा क्या रह जाएगी?

भारत के लिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली ने क्वॉड को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति का अहम हिस्सा बनाया है। लेकिन ट्रंप की चीन यात्रा यह संकेत देती है कि अंततः अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही निर्णय लेगा। यदि आर्थिक या सामरिक कारणों से उसे चीन के साथ समझौता करना पड़े, तो वह पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में भारत को यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति स्थायी मित्रताओं से अधिक स्थायी हितों पर चलती है।

ट्रंप की यात्रा ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं है। यह तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, दुर्लभ खनिज, चिप निर्माण, समुद्री मार्गों और वैश्विक प्रभाव की व्यापक लड़ाई बन चुकी है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। अमेरिका चीन को रोकना चाहता है, लेकिन उसकी कंपनियां चीन के बाजार और विनिर्माण क्षमता से अलग नहीं हो पा रहीं। दूसरी ओर चीन अमेरिकी तकनीक और वैश्विक वित्तीय संरचना से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।

इसीलिए बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात केवल दो नेताओं की बैठक नहीं थी। यह उस नई विश्व व्यवस्था की झलक थी जिसमें प्रतिद्वंद्विता और सहयोग साथ-साथ चलेंगे। दोनों देश सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चुनौती देंगे, लेकिन आर्थिक और तकनीकी स्तर पर पूरी तरह अलग भी नहीं होंगे।

इस पूरी प्रक्रिया में भारत की स्थिति बेहद जटिल हो जाती है। एक ओर वह अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखता है और चीन के साथ संवाद भी बनाए हुए है। ट्रंप की चीन यात्रा भारत को यह संदेश भी देती है कि वैश्विक राजनीति में किसी एक धुरी पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है।

बहरहाल, ट्रंप की बीजिंग यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की विश्व राजनीति का केंद्र अब अमेरिका चीन संबंध ही होंगे। यही संबंध तय करेंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, तकनीकी नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा और भविष्य की विश्व व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन इसके साथ ही यह यात्रा एक बड़ा सवाल भी छोड़ गई है कि यदि अमेरिका खुद चीन के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ रहा है, तो फिर दुनिया के बाकी देशों से वह किस प्रकार की रणनीतिक निष्ठा की अपेक्षा कर सकता है?(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

अभिव्यक्ति की आजादी के आवरण में फैलती ईशनिंदा

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

चुनावी बयार के बाद सनातन विरोधियों के स्वर एक बार फिर मुखरित होने लगे हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने फिर से सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। है। इस दौरान राज्य के नए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय उर्फ जोसेफ विजय चंद्रशेखर भी सदन में मौजूद थे जिन्होंने पूरे भाषण को ध्यान से सुना ही नहीं बल्कि अन्त में हाथ जोडकर अपनी सहमति भी जताई। विगत 2023 के 2 सितंबर को योजनाबद्ध ढंग से सनातन उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना वायरस का विरोध नहीं कर सकते हैं। हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसी तारतम्य में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तत्कालीन सांसद ए राजा ने भी सनातन धर्म के खिलाफ जमकर जहर उगला था। ए राजा ने कहा था कि सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से करनी चाहिए। इसी तरह हम सनातन धर्म का भी विरोध नहीं कर सकते, इसे खत्म करना है। उस समय आपत्तिजनक टिप्पणी से सनातन परम्पराओं को मानने वालों की भावनायें ही आहत नहीं हुई थी बल्कि सम्प्रदायगत संघर्ष की स्थितियां भी निर्मित होने लगीं थी तब विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के 14 पूर्व न्यायाधीशों, 130 पूर्व नौकरशाहों और 118 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर्स सहित देश के 262 प्रतिष्ठित नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर तमिलनाडु सरकार में तत्कालीन मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म करने वाली टिप्पणी पर संज्ञान लेने का आग्रह किया था। उन्हीं उदयनिधि स्टालिन द्वारा अब विधानसभा में दिये गये वक्तव्य का समर्थन करते हुए सत्ताधारी तमिलगा वेट्री कज़गम यानी टीवीके पार्टी के विधायक वी.एम.एस. मुस्तफा ने आग में घी का काम किया है। उल्लेखनीय है कि वंशवादी परम्परा से जन्मजात नेता बनने वाले उदयनिधि स्टालिन के पिता मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन यानी एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके भी पिता मुथुवेल करुणानिधि उर्फ एम करुणानिधि भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तमिलनाडु के इसाई वेल्लार समुदाय के इस परिवार ने हमेशा ही सनातन का खुला विरोध ही नहीं किया बल्कि धर्मगत युद्ध का धरातल तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोडी। इतिहास गवाह है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के आधार पर समूची सृष्टि के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले सनानत धर्म की शाश्वत उपस्थिति के संकेत आदिकाल से ही मिलते रहे हैं जिसे महात्मा मूसा ने 3000 वर्ष पूर्व बाइबल ओल्ड टेस्टामेन्ट में, महात्मा जरथुस्त्र ने 2700 वर्ष पूर्व अवेस्ता में, भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व सूत्रग्रन्थ में, महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व त्रिपिटक में, ईसा मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व बाइबल न्यू टेस्टामेंट में, हजरत मुहम्मद साहब ने 1400 वर्ष पूर्व कुरान शरीफ में, आदिगुरु शंकराचार्य ने 1200 वर्ष पूर्व, संत कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व, गुरु नानक देव ने 500 वर्ष पूर्व, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 200 वर्ष पूर्व तथा स्वामी परमानन्द जी ने लगभग 100 वर्ष पूर्व पुष्ट ही किया है। प्रेम, सौहार्द, अपनत्व और भाईचारा की आधारशिला पर स्थापित सनातन पर संकीर्ण मानसिकता के विभाजनाकारियों द्वारा हमेशा ही आघात किया जाता रहा है। शक्ति, सत्ता और षडयंत्रों का सहारा लेकर हमेशा से ही मीरजाफरों की जमातों ने अपने करतब दिखाने की कोशिशें की हैं। राजनैतिक खेमे ने तो हमेशा ही गिरगिट को अपना आदर्श माना है। चुनावी दौर में माला, मंत्र और मंदिरों का ढोंग रचा। जालीदार टोपी पहनकर मजारों पर चादर चढाई। सफेद पोशाक में मोमबत्ती लेकर चर्चो में गये। जातिगत देवताओं के देवालयों में माथा टेका। अभिनय की चरमसीमा पर पहुंच चुके राजनेताओं की अनेक जमातें वर्तमान के वैश्विक अशान्ति काल में भी अपने षडयंत्रों को अल्पविराम तक नहीं दे रहीं हैं। जन्मजात नेताओं के साथ-साथ सम्प्रदायगत, जातिगत, उपजातिगत, भाषागत, क्षेत्रगत नेताओं की बाढ सी आ गई है। राष्ट्रधर्म को तिलांजलि देकर ये सभी रंगे सियार विभाजनकारी षडयंत्र करने में जुटे हैं।

प्रदूषण, बाजार और बदलती आदतों के बीच पर्यावरण संकट, जिम्मेदारी सिर्फ आम लोगों की नहीं

(कुशाग्र राजेंद्र)

आज हम ऐसे दौर में हैं जहां पर्यावरणीय संकटों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। नदियां कचरे और रासायनिक गंदगी का बोझ ढो रही हैं। कचरे के पहाड़ हमारे ही मोहल्लों की सरहद पर उग आए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस दबाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। यह सब दूर के भविष्य की चेतावनी नहीं, यह अब हमारा वर्तमान है।गौर करें तो पाएंगे कि प्रकृति और संसाधन के साथ जो हमारा संबंध था, वह पूरी तरह बदल गया है। हमारी आदतें बदल गई हैं। प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते बदलने के कई कारण हैं। विकास का वैश्विक मॉडल, आर्थिक नीतियां, बाजारवाद, वर्तमान शहर नियोजन और डिजिटल एल्गोरिद्म एक साथ मिल कर हमारी आदतें बदल रहे हैं।

मगर व्यवस्था में बदलाव को नजरअंदाज कर अच्छी आदतों के साथ पर्यावरण संरक्षण का सारा बोझ आम लोगों के कंधों पर डालने की परिपाटी है। हर व्यक्ति अपनी कुछ आदतें बदलें, तभी पर्यावरणीय संकट से निजात मिल सकती है। बत्ती बंद कीजिए, पानी बचाइए, कचरा अलग कीजिए, कपड़े सोच-समझ कर खरीदिए, कार की जगह बस और मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए इत्यादि। जैसे लगता है कि मौजूदा संकट केवल आम लोगों की आदतों का ही परिणाम हो।

हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ज्यादातर बड़े संकट जैसे प्रदूषण, वैश्विक ताप इत्यादि के मूल में पिछले कई दशकों से अपनाई गई व्यवस्था है। मगर सरलीकरण का आलम यह है कि अंगुली सबसे पहले आम लोगों की आदतों पर उठती है। जलवायु परिवर्तन से लेकर पानी, ऊर्जा और कचरे के सवाल तक, सार्वजनिक विमर्श में अक्सर यह संदेश गूंजता है कि अगर आम लोग थोड़ी 'अच्छी आदतें' अपना लें, तो हालात बदल सकते हैं। नल बंद रखिए, प्लास्टिक थैला छोड़िए, साइकिल चलाइए, ये सब जरूरी बातें हैं। मगर जब पूरा ध्यान यहीं केंद्रित हो जाता है, तो असली वजह धुंधली होने लगती है। व्यवस्थाजनित संकटों का समाधान केवल व्यक्तिगत संयम में खोजना एक तरह से जिम्मेदारी के बड़े हिस्से को अदृश्य कर देना भी है।

पानी का सवाल उठाइए, तो चर्चा अक्सर हमारे स्नानागार और रसोई से शुरू होती है। सलाह दी जाती है कि ब्रश करते समय नल न बहने दें, बाल्टी से नहाएं,

पाइप से गाड़ी न धोएं। इन सबका महत्त्व कम नहीं है, लेकिन वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जल-उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा खेती, उद्योग और शहरी आपूर्ति व्यवस्था में खपता है, जबकि घरेलू उपयोग उसका छोटा अंश है। खेतों तक जाने वाली नहरों में यदि जगह-जगह रिसाव हों, शहरों की पाइपलाइनें वर्षों से मरम्मत के बिना पानी बहाती रहें और उद्योग अपना गंदा पानी बिना शोधन के नदियों में छोड़ते रहें, तो अकेले घरों का अनुशासन कुल तस्वीर को कितना ही बदल पाएगा।

फिर भी जागरूकता अभियानों में दिखाई देता है- टपकता नल और ब्रश करता बच्चा, न कि रिसाव वाली नहर या अंधेरे में चुपचाप नदी की ओर बहता फैक्टरी का नाला।

ऊर्जा मामले में भी यही कहानी दोहराई जाती है। सवाल है कि ऊर्जा-उपभोग और उत्सर्जन की सबसे बड़ी मांग कहां से आ रही है। भारी उद्योग, सीमेंट, इस्पात और रसायन उद्योग, डेटा सेंटर, विमानन तथा मालवाहक जहाज, ये सारे क्षेत्र मिल कर ऊर्जा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी निगलते हैं, जबकि घरेलू स्तर की बचत का दायरा संरचनात्मक सहयोग के बिना सीमित रह जाता है।

उपभोग के मोर्चे पर हम सब एक खालिस उपभोक्ता बनते जा रहे हैं। बाजार व्यवस्था की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है। बाजार में उपलब्ध अधिकतर उत्पाद इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी उम्र सीमित रहे। मरम्मत कठिन या महंगी हो और उपभोक्ता कुछ ही वर्षों में नया सामान लेने को प्रेरित हो जाए। मोबाइल फोन और टीवी से लेकर घरेलू उपकरणों तक यह प्रवृत्ति अब औद्योगिक मॉडल का हिस्सा बन चुकी है।

उपभोक्ताओं से कहा जाता है कि कम खरीदिए, सोच-समझ कर खरीदिए, लेकिन जब दुकान में टिकाऊ और मरम्मत-योग्य विकल्प लगभग नदारद हों तथा सस्ते वही सामान हों जो जल्दी टूटने के लिए बनाए गए हों, तो जिम्मेदार उपभोग की नैतिकता भी अपने आप में अधूरी हो जाती है।

'इस्तेमाल करो और फेंको' की व्यवस्था ने हमारी प्रकृति सम्मत आदतों की जमीन ही बदल दी। बोतलबंद पानी से लेकर सुविधाजनक पैकेजिंग और तेज वितरण ने जीवन को निस्संदेह आसान बनाया, पर बदले में प्लास्टिक, थर्मोकोल और ई-कचरे के पहाड़ खड़े कर दिए। ऑनलाइन बाजारों ने एक कदम और आगे बढ़ कर प्रचार-रणनीतियों से हमारी इच्छाओं का नक्शा तक अपने हाथों में ले लिया है। 'केवल आज की विशेष छूट' और 'बस दो पीस बचे हैं' जैसी तरकीबें यह सुनिश्चित करती हैं कि जरूरत और चाहत के बीच की रेखा लगातार धुंधली होती जाए।

नए शहरों के नियोजन में भी इसी तरह का विरोधाभास दिखाई देता है। सार्वजनिक अपील यह होती है कि लोग निजी वाहन कम चलाएं, बस और मेट्रो का उपयोग करें। आसपास जाने के लिए साइकिल चलाएं और पैदल चलें। मगर जैसे-जैसे शहरों का विस्तार हुआ है, नई आबादी ज्यादातर उन इलाकों में बसाई गई हैं जहां न भरोसेमंद बस सेवा है, न मेट्रो और न साइकिल पथ। ऐसी स्थिति में निजी वाहन विकल्प नहीं, मजबूरी बन जाता है।

आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग इस मजबूरी को कार और दोपहिया से संभाल लेता है। जो नहीं संभाल पाते वे रोजमर्रा की यात्रा में समय और सुरक्षा दोनों की ऊंची कीमत चुकाते हैं। बाद में यही लोग भीड़ और प्रदूषण बढ़ाने वाले नागरिकों की श्रेणी में रख दिए जाते हैं, जबकि शहर की मौलिक योजना और परिवहन नीति पर सवाल अपेक्षाकृत कम ही उठते हैं।

डिजिटल दौर में 'फुटप्रिंट' की भाषा, चाहे वह कार्बन की हो या डेटा की, तेजी से लोकप्रिय हुई है। ऐप बताने लगते हैं कि आपकी हर उड़ान, हर भोजन, हर खरीदारी से कितनी अतिरिक्त मात्रा में उत्सर्जन जुड़ रहा है। यह जानकारी उपयोगी है, क्योंकि वह हमारी रोजमर्रा की आदतों को देखने की एक नई दृष्टि देती है, लेकिन जब पूरा नैतिक दायरा केवल व्यक्ति तक सिमट जाता है, तो उत्पादन प्रणालियों, ऊर्जा स्रोतों, व्यापार नियमों और नियामक ढांचों की भूमिका छिप जाती है। सामने दिखता रहता है- केवल गैर-जिम्मेदार उपभोक्ता।

यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि व्यक्ति की जिम्मेदारी शून्य है। हर किसी के पास कुछ न कुछ विकल्प होते हैं और हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। निजी जीवन में संयम, संसाधनों का सम्मान, पुनः उपयोग, मरम्मत और साझा उपयोग जैसी आदतें न केवल प्रतीकात्मक हैं, बल्कि व्यावहारिक भी हैं।

संकट मौजूदा आर्थिक व्यवस्था और विकास के प्रारूप के हैं, तो समाधान भी व्यवस्था के स्तर पर ही निकलेंगे, हालांकि उनकी शुरुआत व्यक्ति से होकर ही गुजरती है। जरूरत उस संतुलित दृष्टि की है जिसमें हम न तो सारी उम्मीद 'ऊपर की शक्तियों' पर छोड़ दें, न ही पूरा नैतिक बोझ केवल आम नागरिकों पर डाल दें।

जब व्यक्तिगत नैतिकता और व्यवस्थागत बदलाव एक-दूसरे के पूरक की तरह देखे जाएं, तभी यह उम्मीद की जा सकती है कि हमारी सामूहिक शक्ति सचमुच उस दिशा में काम करेगी जहां पृथ्वी, समाज और भविष्य, तीनों के हित एक साथ बचाए जा सकें। (यह लेखक के अपने विचार है)

संक्षिप्त समाचार

अवमानना के बढ़ते प्रकरणों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर सूर्यकांत सीजेआई

रायपुर। हैदराबाद में आयोजित हाल ही में न्यायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत ने राज्य सरकारों द्वारा हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों पर उनके विरुद्ध दिये जा रहे फैसले का पालन करने में टाल मटोल करने पर चिंता व्यक्त की है। सीजेआई सूर्यकांत ने विधिक सम्मेलन में अनेक राज्यों से आए अधिवक्ताओं एवं विधिक विशेषज्ञों के बीच कहा कि अवमानना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर केंद्र एवं राज्य सरकार को चिंतन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार राज्य सरकारों के समर्थन में फैसले नहीं आते तो वह हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अवमानना याचिकाओं पर अप्रत्यक्ष में नाराजगी व्यक्त करते है। बिहार उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मप्र एवं छग में उच्च न्यायालयों में अनेक संगठनों द्वारा उनकी याचिका पर फैसला सरकार के विरुद्ध आता है तो राज्य सरकारें इसे लागू नहीं करती जबकि संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकारों का यह दायित्व है कि वह प्रजातंत्र के तीसरे खंभे न्यायापालिका जो सजग प्रहरी भी है के न्यायाधीशों द्वारा दिये गये मामलों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि वैसे भी उच्च न्यायालयों एवं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामले करोड़ों की संख्या में है।

कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट खराब होने से फंसे बीजेपी नेता सहित कई लोग

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लिफ्टकांड हो गया. रजबंधा मैदान स्थित निजी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को अचानक लिफ्ट खराब हो गई, जिसमें भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी समेत 7 लोग अंदर लगभग 15 मिनट तक फंसे रहे. मौके पर हड़कंप मच गया. किसी तरह सुरक्षा गार्ड ने दरवाजे खुलवाकर उन्हें बाहर निकाला. घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कॉम्पलेक्स प्रबंधन पर ठिकरा फोड़ा. भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस कॉम्प्लेक्स में पहले भी लिफ्ट खराब होने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं. कभी बुजुर्ग तो कभी महिलाएं यहां लिफ्ट में फंस जाती हैं. उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने प्रशासन से नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, निजी कॉम्प्लेक्स में भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी और अन्य लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे. इस दौरान लिफ्ट अचानक बंद हो गया. सभी ने बार-बार अलार्म और फोन से मदद मांगने की कोशिश की, हालांकि तत्काल किसी प्रकार की तकनीकी सहायता नहीं मिल सकी. बाद में कॉम्पलेक्स के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों ने मशक्कत कर लिफ्ट का गेट खुलवाया. इसके बाद सभी सुरक्षित बाहर निकल गए।

शादी में गया परिवार, पीछे टूटा ताला; 24 मामलों वाला शातिर चोर गिरफ्तार

रायपुर। रिश्तेदार की शादी में गया परिवार जब घर लौटा तो ताले टूटे थे, पेटी खाली थी और घर का सामान गायब था, लेकिन गांधीनगर पुलिस ने कुछ ही दिनों में ऐसा शिकंजा कसा कि 24 मामलों में शामिल शातिर चोर आखिरकार पकड़ में आ गया। सरगुजा जिले के थाना गांधीनगर क्षेत्र में हाई स्कूल के पीछे स्थित मकान में हुई इस चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। प्रार्थी 14 मई 2026 को अपने घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में शादी समारोह में गया था। 17 मई को वापस लौटने पर उसने देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे और पेटी का ताला टूटा हुआ है। घर में रखे एक सोने का लॉकेट, दो नग कान की बाली, 2000 रुपए नगद और चावल की बोरी चोरी हो चुकी थी। शिकायत मिलते ही थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 285/2026 के तहत धारा 331(4), 305ए बीएनएस में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस टीम लगातार संदिग्धों की तलाश कर रही थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि बनारस रोड पेट्रोल पंप के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर भज्जू वासुदेव को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की पूरी वारदात कबूल कर ली और बताया कि चोरी का सामान खेत में छिपाकर रखा है।

चरित्र शक में पत्नी की हत्या चार मासूम अनाथ हुए आरोपी पति गिरफ्तार

रायपुर। चरित्र शंका ने एक हंसते-खेलते परिवार को पलभर में तबाह कर दिया, पति ने पत्नी को डंडे से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया और पीछे छूट गए चार मासूम बच्चे, जिनकी आंखों के सामने उनका पूरा संसार उजड़ गया। कोरिया जिले के थाना पटना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परसाभारी बुढार में 18 मई 2026 को हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मामले में प्रार्थी जगमोहन पंडो पिता स्वर्गीय भंडारी पंडो निवासी ग्राम परसाभारी बुढार ने थाना पटना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी रंगसाय पंडो ने अपनी पत्नी सोनामती पंडो पर चरित्र शंका करते हुए डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी रंगसाय पंडो ग्राम परसाभारी बुढार थाना पटना जिला कोरिया का रहने वाला है।

आत्मनिर्भरता, पोषण और बदलाव की नई पहचान बनीं महिला स्व-सहायता समूह

पूरक पोषण आहार निर्माण का कार्य अब महिलाओं के हाथो

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति को एक साथ जोड़ते हुए राज्य सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता की नई रोशनी जगाई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी-टू-ईट) के निर्माण एवं वितरण का दायित्व महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपकर सरकार ने महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के समन्वित मॉडल के रूप में उभर रही है। पहले जहां पूरक पोषण आहार निर्माण का कार्य बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता था, वहीं अब यह जिम्मेदारी गांव की महिलाओं ने संभाल ली है, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हुआ है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलें में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। इन छह जिलें के 42 महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट पोषण आहार निर्माण एवं वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार मिली है और वे अब संगठित रूप से उत्पादन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण का कार्य संभाल रही हैं। प्रदेश का पहला रेडी-टू-ईट उत्पादन रायगढ़ जिले में प्रारंभ हुआ, जिसने पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरबा जिले में 10, रायगढ़ में 10, सूरजपुर एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में 7-7, बस्तर में 6 तथा दंतेवाड़ा में 2 महिला स्व-सहायता समूह इस कार्य से जुड़ी हुई हैं। इन समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है। इस पहल का सबसे

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा भी बनी हैं। उत्पादन इकाइयों में कार्यरत महिलाओं को मशीन संचालन, गुणवत्ता परीक्षण, पैकेजिंग, भंडारण वितरण और लेखा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित इन इकाइयों ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। सूरजपुर जिले में संचालित रेडी-टू-ईट निर्माण संयंत्र इस बदलाव की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। भैयाथान, प्रतापपुर और सूरजपुर विकासखंडों में संचालित संयंत्रों में महिलाएं पौष्टिक नमकीन दलिया और मीठा शक्ति आहार तैयार कर रही हैं। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन 'ए', विटामिन 'डी', आयरन, कैल्शियम, जिंक और फोलिक एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं, जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इन संयंत्रों में कार्यरत महिलाएं अब केवल अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहीं, बल्कि जिले के पोषण अभियान में महत्वपूर्ण भागीदार बन चुकी हैं। सूरजपुर जिले में निर्माण के साथ-साथ वितरण की जिम्मेदारी भी महिला समूहों को सौंपी गई है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं आजीविका से जुड़ सकी हैं। लगभग 430 महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों तक पोषण आहार पहुंचाने के कार्य में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पहल को महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और बच्चों के बेहतर पोषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना है कि यह योजना महिलाओं को रोजगार देने के साथ-साथ राज्य के पोषण स्तर में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दरअसल, यह पहल केवल पोषण आहार निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की एक सशक्त कहानी भी है, जिन महिलाओं की पहचान कभी केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थी, वे आज उत्पादन इकाइयों का संचालन कर रही हैं।

आमासिवनी में युवक का मर्डर लाइव वीडियो आया सामने......

रायपुर/ संवाददाता

राजधानी रायपुर के आमासिवनी इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हुई खूनी झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला आमासिवनी स्थित विधानसभा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पैसे की लेनदेन को लेकर हुए विवाद के बाद तीन बदमाशों ने मिलकर युवक सुकृत खांडे की बेरहमी से हत्या कर दी, युवक की खून से साणे इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए राकेश गुप्ता उर्फपानी, देवदास उर्फहड्डी, विनोद उर्फविक्की और एक 16 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान सुकृत खांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुकृत खांडे का दिन के समय राकेश पांडे उर्फपानी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन रात होते-होते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश और दिन में हुए विवाद को लेकर दोनों गुट आमने-सामने आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात में दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर बहस हुई, जिसके बाद आरोपियों ने सुकृत खांडे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश में दबिश दी।

भीषण गर्मी से बेहाल हाथी ने सूंड से खुद पर की पानी की बौछार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब वन्यजीवों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ते तापमान और जंगलों में सूखते जलस्रोतों के बीच वन्यजीव पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों की ओर पहुंच रहे हैं। इसी बीच रायगढ़ और ओडिशा सीमा क्षेत्र से एक हाथी का दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक एक जंगली हाथी गांव के पास बने जलस्रोत तक पहुंचा, जहां उसने गर्मी से राहत पाने के लिए अपनी सूंड से बार-बार शरीर पर पानी की बौछार की। हाथी का यह अनोखा अंदाज वहां मौजूद ग्रामीणों को आकर्षित कर गया। लोगों ने इस पूरे दृश्य को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

संग्राहकों को हो रहा है सीधा ऑनलाइन भुगतान

अबूझमाड़ में महुआ प्रसंस्करण के लिए बनेगा जनजातीय सहकारी मॉडल.........

- आदिवासी समुदाय की अतिरिक्त आय हेतु लघु वनोपज संघ की बैठक में विचार-विमर्श

रायपुर/ संवाददाता

अबूझमाड़ क्षेत्र के विकास और वहां जनजातीय (आदिवासी) नेतृत्व में महुआ प्रसंस्करण के लिए एक प्रभावी सहकारी मॉडल विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में समर्थन मूल्य पर तेंदूपत्ता संग्रहण तथा आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए वन धन योजना और ट्राईफेड के तहत महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की कार्ययोजना पर भी विमर्श किया गया। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय (महानदी भवन) में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वन धन सहकारी समितियों द्वारा महुआ के फूलों से विभिन्न प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। महुआ लड्डू और कुकीज, महुआ स्क्वैश (शरबत), महुआ का अचार और महुआ उत्पादों की प्रोसेसिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया। बैठक में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य की भी समीक्षा की गई। इस दौरान संग्रहण से जुड़े व्यापार में सरकार को वित्तीय हानि से बचाने और संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभांश पहुंचाने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा वर्तमान में संग्राहकों को पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत सीधे ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट......

- तेज आंधी और हवाओं से बढ़ेगी मुश्किलें

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भीषण गर्मी और उमस के बीच अब प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और गरज-चमक का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और विदर्भ क्षेत्र में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम का असर प्रदेश के मौसम पर साफ दिखाई दे रहा है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट और मौसम में नमी बढ़ने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बस्तर, दुर्ग, महासमुंद और आसपास के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। राजधानी रायपुर में शनिवार को 62.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि बस्तर संभाग के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दिनभर बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना रहा। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने भी इस बारिश को राहत भरी बताया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और बादलों की सक्रियता के कारण अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिम विदर्भ से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जो लगातार नमी को मध्य भारत और छत्तीसगढ़ की ओर खींच रही है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय गरिमा उत्सव अभियान शुरू, गांव-गांव पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं

रायपुर। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के निर्देशानुसार 'जनजातीय गरिमा उत्सव' के अंतर्गत 'जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले' थीम पर आधारित अभियान का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ किया गया। यह अभियान मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, जनजातीय गरिमा उत्सव प्रदेश के जनजातीय बसाहटों के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में जनजातीय क्षेत्रों का विकास बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे मजबूत नींव पर ही मजबूत भवन तैयार होता है, उसी प्रकार विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय गांवों का शत-प्रतिशत विकास आधारशिला का कार्य करेगा। मंत्री नेताम ने बताया कि पीएम जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान और सर्वेसेतु ऐप में बेहतर प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है। उन्होंने अधिकारियों से अभियान के मूल उद्देश्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आह्वान किया। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और आयुक्त डी. राहुल वेकंट के नेतृत्व में अभियान की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है।

विधानसभा को पेपरलेस करने के कार्यों में आएगी तेजी सचिव बंसल

- लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विधानसभा भवन का किया निरीक्षण
- पर्याप्त पार्किंग के साथ सर्वसुविधायुक्त ड्राइवर-रूम बनाने के दिए निर्देश

रायपुर/ संवाददाता

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोकभवन (राजभवन) के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे परिसर का भ्रमण कर ले-आउट और फ्लोर-प्लान जाना। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री बंसल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा को 'पेपरलेस' बनाने के लिए तकनीकी कार्यों और व्यवस्थाओं में तेजी लाने लोक निर्माण विभाग और चिप्स को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता श्री टी.आर. कुंजाम, अधीक्षण अभियंता श्री डी.के. नेताम और कार्यपालन अभियंता श्री अभिनव श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद थे। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने 'लोकभवन' का निर्माण राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप उत्कृष्टता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे परिसर के सौंदर्य, सूरज की रोशनी और पूर्ण उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने भवन की सभी बारीकियों पर पुख्ता काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए यहां बन रहे सभा-भवनों और कार्यालयीन कक्षों की बैठक व्यवस्था पहले से ही निर्धारित कर उनके अनुरूप कार्यों को अंजाम देने को कहा। उन्होंने भवन के निर्माण कार्य में लगे अलग-अलग एजेंसियों से कार्य प्रगति की जानकारी लेकर यथाशीघ्र सभी कार्य पूर्ण कर इसे लोक निर्माण विभाग को हैंड-ओवर करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने नए विधानसभा भवन में प्रवेश द्वार, सदन, अधिकारी दीर्घा, लॉबी, डाइनिंग एरिया, मीडिया ब्रीफिंग एरिया, समिति कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, उप मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों के कार्यालयों, ऑफिसर लाउंज और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यालयीन कक्षों में समुचित फर्नीचर और बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत ग्राम चंदौरा में आयोजित

जनसमस्या निवारण शिविर में 319 आवेदन प्राप्त हुए और 114 का मौके पर निराकरण किया गया

- जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना, शासन का उद्देश्य: प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल

रायपुर/ संवाददाता

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिले के प्रतापपुर जनपद पंचायत के ग्राम चंदौरा में आज जनसमस्या निवारण शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सूरजपुर जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयालदास बघेल ने की, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं मांगें प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कीं। शिविर में कुल 319 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 114 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। ग्रामवासियों को सम्बोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि अधिक से अधिक लोग सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित शिविरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन ने पारदर्शिता के साथ धान खरीदी की है तथा किसानों को राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। राज्य के जरूरतमंद एवं कमजोर वर्गों को नियमित रूप से खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्होंने किसानों से मिट्टी परीक्षण कराने एवं शासन की योजनाओं के तहत खाद-बीज प्राप्त करने की अपील की।

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी का बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफः अमर अग्रवाल ने की कड़ी निंदा

बिलासपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे अत्यंत शर्मनाक,

दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर आसीन नेताओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार इस प्रकार की बयानबाजी उनकी नकारात्मक एवं द्वेषपूर्ण राजनीति को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश गर्व महसूस करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के 32 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुए हैं। यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, मजबूत नेतृत्व और विश्व मंच पर देश की सशक्त उपस्थिति का प्रतीक है। श्री अमर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान प्रत्येक भारतीय का सम्मान है। उनके नेतृत्व में भारत एक मजबूत और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा लगातार अपशब्दों का प्रयोग अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति को पहले भी नकार चुकी है और आगे भी इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और संसाधनों की बचत के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाई कोर्ट प्रशासन ने विशेष सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अवकाश अवधि में मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जारी परिपत्र के अनुसार, भीषण गर्मी को देखते हुए अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय आने से राहत देने के लिए ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट प्रशासन का मानना है कि इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसके लिए कार्यालयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हों। घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य आधिकारिक माध्यमों से लगातार उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संसाधनों और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार-पूलिंग व्यवस्था अपनाने की भी सलाह दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों को भी इस व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई कोर्ट प्रशासन ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित तकनीकी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित रजिस्ट्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

नौकरी पाने के चक्कर में युवक पैसा गंवा बैठा,किया सुसाइड

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और प्रताड़ना से तंग आकर युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले युवक के लाचार पिता ने अब प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद थक-हारकर कलेक्टर जनदर्शन में न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम हिरी निवासी रमेश साहू ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनदर्शन में अपनी पीड़ा सुनाई। उन्होंने बताया कि भवानी वैष्णव ने अप्रैल 2025 में बेटे राहुल साहू को रेलवे मेस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके एवज में पीड़ित पिता ने अपनी काश्तकारी भूमि को गिरवी रखकर कुल पांच लाख रुपए नगद आरोपित दंपत्ति को सौंपे थे। आरोपितों ने छह महीने के भीतर नौकरी लगाने का खोखला आश्वासन दिया था। समय बीतने के बाद जब नौकरी नहीं लगी, तो पीड़ित पक्ष को ठगी का अहसास हुआ। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपित भवानी वैष्णव और उसकी पत्नी ने रुपए लौटाने से साफमना कर दिया और उल्टा राहुल को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर डराने-धमकाने लगे।

सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम रामपुर में जनसमस्या निवारण शिविर में की शिरकत,ग्रामीणों से किया गया सीधा संवाद.......

- 66.99 करोड़ रुपये की लागत के 87 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास, 116 हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री प्रदाय
- जनता जनार्दन से मिलकर मिलती है काम करने की नई ऊर्जा- मुख्यमंत्री'

सूरजपुर। संवाददाता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जनपद पंचायत रामानुजनगर के ग्राम रामपुर में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर में शिरकत कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया तथा उनकी समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 66.99 करोड़ रुपये की लागत के कुल 87 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को महत्वपूर्ण सौगात प्रदान की। उन्होंने शिविर स्थल पर लगे विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा 116 हितग्राहियों को सहायता राशि एवं सामग्री का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति प्रबल जनभागीदारी एवं शासन के प्रति अटूट विश्वास को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार बनाई है और सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंचकर यह जानने का प्रयास कर रही है कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम

पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंच रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सूरजपुर का यह उनका 11वां जिला प्रवास है तथा 10 जून तक प्रदेश के सभी 33 जिलों के दौरे का लक्ष्य निर्धारित है। प्रत्येक जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं लंबित मामलों की समीक्षा की जा रही है तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ही समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। औचक निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं की सतत निगरानी भी की जा रही है तथा नागरिक सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहक माताओं-बहनों को चरण पादुका योजना के तहत वितरित किए जा रहे जूतों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में ग्रामीण नंगे पैर जंगल जाते थे, अब इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने किसानों को 3716 करोड़ रुपये बोनस वितरण का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है तथा लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित महिलाओं से योजना की राशि नियमित रूप से प्राप्त होने की जानकारी भी ली।

ट्रेनों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु बिलासपुर रेल मंडल में विशेष संरक्षा अभियान

- संरक्षा विभाग की सक्रिय पहल : फायर सेफ्टी सिस्टम एवं प्रशिक्षण पर विशेष जोर

बिलासपुर। बिलासपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग द्वारा ट्रेनों में आगजनी की संभावित घटनाओं की रोकथाम, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रेल संपत्ति की संरक्षा के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विशेष संरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मंडल के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों एवं गुजरने वाली ट्रेनों में युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एवं यात्री ट्रेनों सहित मंडल से प्रारंभ होने वाली ट्रेनों में विशेष संरक्षा जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान संरक्षा विभाग द्वारा कोचों, पावर कार, पैंट्री कार एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का गहन निरीक्षण किया गया। अभियान के अंतर्गत एसी कोचों में फायर एक्सटिंग्विशर की उपलब्धता एवं कार्यशीलता की जांच, फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन सिस्टम (स्नष्ठस्स/स्नस्ष्ठस) की जांच, पावर कारों में विद्युत सुरक्षा संबंधी निरीक्षण, वायरिंग चेक, अर्थ लीकेज चेक, एमसीबी एवं विद्युत पैनलों की जांच, थर्मल स्कैनिंग, बैटरी एवं जंक्शन बॉक्स

की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त पैंट्री कार एवं पावर कार में फायर डिटेक्शन एवं फायर सप्रेशन सिस्टम की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित की गई। ट्रेनों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, फायर बॉल एवं एयरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली, अग्निशमन यंत्रों की वैधता एवं उपयोगिता की भी विशेष जांच की गई। संरक्षा विभाग द्वारा ऑन बोर्ड स्टाफ, कोच अटेंडेंट, टीटीई, पैंट्री कार स्टाफ एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों को फायर फाइटिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, यात्रियों की सुरक्षित निकासी एवं प्रारंभिक अग्निशमन संबंधी विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

छतीसगढ़िया क्रांतिसेना और जेसीपी प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर। बलौदाबाजार आगजनी कांड मामले में गिरफ्तार छतीसगढ़िया क्रांतिसेना और जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे अमित की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बलौदा बाजार कोतवाली पुलिस ने अमित बघेल को आगजनी और हिंसा से जुड़े अलग-अलग मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहले निचली अदालत में जमानत की मांग की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, यह पूरा मामला बलौदा बाजार हिंसा कांड से जुड़ा है। 15 और 16 मई 2024 की रात गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इस घटना के विरोध में 10 जून को हजारों लोग बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए थे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति हिंसक हो गई और उपद्रवियों ने कलेक्टर व एसपी कार्यालय में आग लगा दी थी। इस आगजनी में सरकारी संपत्तियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा था। इसी मामले में पुलिस ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। याचिका में अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत देने की मांग की गई थी। हालांकि मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामले में अन्य आरोपियों से उनकी स्थिति अलग है, उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले भी लंबित हैं। इसी आधार पर अदालत ने समानता का दावा स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि अमित बघेल के खिलाफकुल 17 मामले लंबित हैं। वहीं सह आरोपी अजय यादव के खिलाफ 13 और दिनेश कुमार वर्मा के खिलाफएक अन्य मामला दर्ज है। अदालत ने कहा कि लंबित मामलों और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मामले में संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाती है या आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूरी हो जाती है, तो आरोपी दोबारा जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत के इस फैसले के बाद अमित बघेल को अब जेल में ही रहना होगा।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और संसाधनों की बचत के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाई कोर्ट प्रशासन ने विशेष सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अवकाश अवधि में मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जारी परिपत्र के अनुसार, भीषण गर्मी को देखते हुए अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय आने से राहत देने के लिए ऑनलाइन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट प्रशासन का मानना है कि इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इसके लिए कार्यालयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि न्यायालयीन कार्य प्रभावित न हों। घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य आधिकारिक माध्यमों से लगातार उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संसाधनों और ईंधन की बचत को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार-पूलिंग व्यवस्था अपनाने की भी सलाह दी गई है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायाधीशों को भी इस व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने बढ़ाया दिव्यांग बेटी का हौसला एक व्हील चेयर ने कम कर दी मां की वर्षों पुरानी चिंता....

- व्हील चेयर मिलने से बदली दिव्यांग बेटी की जिंदगी मां की आंखों में छलक आई राहत

सूरजपुर संवाददाता। रामपुर शिविर में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम पंचायत सरईपारा निवासी 17 वर्षीय दिव्यांग बालिका रोशनी को व्हील चेयर प्रदान की। वर्षों से बेटी को गोद में उठाकर इधर-उधर ले जाने वाली मां अनीता कुर्रे की आंखों में उस समय राहत और खुशी साफदिखाई दे रही थी। रोशनी जन्म से ही दिव्यांग है। वह बहुत कम सुन पाती है और बोल भी नहीं पाती। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए उसकी देखभाल करना आसान नहीं था। मां अनीता और परिवार के अन्य सदस्य उसे गोद में उठाकर ही हर जगह ले जाया करते थे। घर से बाहर ले जाना हो या अस्पताल, हर बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने जब

शिविर में रोशनी और उसकी मां से मुलाकात की, तो उनकी परिस्थितियों को गंभीरता से सुना। इसके बाद उन्होंने तत्काल रोशनी को व्हील चेयर प्रदान की। व्हील चेयर मिलते ही रोशनी के मां के चेहरे पर राहत थी। रोशनी की मां अनीता कुर्रे ने बताया कि उनका परिवार मजदूरी कर घर का खर्च चलाता है। सीमित आय में बेटी की देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना काफी मुश्किल था। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अब व्हील चेयर मिलने से रोशनी को कहीं भी ले जाना आसान हो जाएगा और उसकी जिंदगी कुछ हद तक सहज बन सकेगी। अनीता ने मुख्यमंत्री और शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मदद उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां हर कदम पर परेशानी होती थी, वहीं अब बेटी को संभालने में काफी सुविधा मिलेगी। रामपुर शिविर में संवेदनशील शासन व्यवस्था की तस्वीर थी, जहां जरूरतमंदों की कठिनाइयों को समझते हुए उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी बेटी के लिए मां की आंखों की राहत इस बात का प्रमाण थी कि छोटी-सी मदद भी किसी परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।

कलेक्टर का बिहारपुर अंचल में सघन निरीक्षण दौरा,धरातल पर परखी विकास कार्यों की गुणवत्ता

- पूरक पोषण आहार केंद्र से लेकर एकलव्य विद्यालय तक का किया निरीक्षण
- बांक पर्यटन स्थल के विकास की संभावनाओं पर भी हुआ मंथन

सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने आज जिले के दूरस्थ अंचल बिहारपुर का सघन दौरा कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की धरातलीय हकीकत स्वयं परखी। प्रातः से प्रारंभ हुए इस मैराथन दौरे में कलेक्टर ने पूरक पोषण आहार उत्पादन केंद्र, नवनिर्मित महतारी सदन, नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी नवाटोला , निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय एवं बांक पर्यटन स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने एक-एक तथ्य का गहन आकलन किया तथा जहां भी कमियां पाई गईं, वहां संबंधितों को मौके पर ही कमियों को दूर करने के कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती जमील ने अपने दौरे की शुरुआत ग्राम करकोटु, भैयाथान स्थित पूरक पोषण आहार उत्पादन केंद्र से की। केंद्र में उन्होंने दलिया एवं अन्य पोषण उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया तथा कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तैयार उत्पादों के वितरण तक की समूची व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र से निर्मित होने वाले प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि यह पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तक पहुंचता है, अतः इसकी गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात कलेक्टर ने ग्राम पंचायत ठाढ़पाथर, ओड़गी में नवनिर्मित महतारी सदन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में सामने आई कमियों को चिन्हित करते हुए उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया कि शीघ्रातिशीघ्र सभी आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कराए जाएं। दौरे के क्रम में कलेक्टर श्रीमती जमील ने निर्माणाधीन नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहारपुर के भवन निर्माण कार्य का गहन निरीक्षण किया। निर्माण में पाई गई कमियों पर उन्होंने ठेकेदार को निश्चित समय-सीमा के भीतर सुधार कार्य पूर्ण करने तथा शेष निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण मानकों के कड़ाई से पालन करने की बात कही। अपने दौरे के अगले चरण में कलेक्टर श्रीमती जमील की गाड़ी अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी नवाटोला तक पहुंची, जहां उन्होंने चौकी की समस्त व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरे कार्यरत न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैमरे तत्काल दुरुस्त कराए जाएं तथा चौकी की सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां सतर्क निगरानी एवं चाक-चौबंद सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर ने पालदनौली में निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी विस्तार से निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित ठेकेदार को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण दौरे के अंतिम चरण में कलेक्टर ने जिले के बांक पर्यटन स्थल का भ्रमण किया। उन्होंने रेण नदी पर स्थित मनोरम झरने का अवलोकन किया तथा पर्यटन की दृष्टि से बांक को और अधिक विकसित किए जाने की संभावनाओं पर उपस्थित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक प्रभावी एवं सुनियोजित प्रचार-प्रसार कार्ययोजना तैयार की जाए।

आबकारी अफसर की नौकरी खतरे में,फर्जी जाति प्रमाणपत्र की जांच शुरू

बिलासपुर। आबकारी अधिकारी के फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने बिलासपुर की जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति को जल्द जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आबकारी अफसर राजेश हेनरी पर आरोप है कि बिलासपुर में बने फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए वह पिछले 35 साल से आबकारी विभाग में नौकरी कर रहे हैं. इस मामले में भोपाल निवासी प्रभात पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें बताया कि मध्यप्रदेश के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त राजेश हेनरी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है. उन्होंने इस संबंध में 22 जून 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन लंबे समय से यह मामला बिलासपुर की जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति के पास लंबित है. याचिका में बताया गया कि सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी के अनुसार उक्त अधिकारी के प्रमाणपत्र में बिलासपुर तहसील के सील और साइन मिले. लेकिन, जब बिलासपुर तहसील कोर्ट के दायरा पंजी में साल 1990-91 के प्रकरण की जानकारी ली गई, तब पता चला कि तहसील कार्यालय में उनके जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण ही दर्ज नहीं है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि, छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने उनके अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र को जांच के लिए जिला स्तरीय समिति को भेजा था. लेकिन, दो साल से अफसर जांच ही नहीं कर रहे.

जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मिशन संचालक ने किया ईरकभट्टी एवं बेचा की पेयजल व्यवस्थाओं का निरीक्षण

अबूझमाड़ के गांवों में उत्साहपूर्वक मनाया गया जल अर्पण कार्यक्रम एवं जल बंधन कार्यक्रम

नारायणपुर। जिले के ओरछा विकासखंड अंतर्गत अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्राम ईरकभट्टी एवं बेचा में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं का भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय मिशन संचालक, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली कमल किशोर सोन तथा एरिया ऑफिसर उमेश भारद्वाज द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों ग्रामों में उत्साह एवं जनभागीदारी के साथ 'जल अर्पण कार्यक्रम' एवं 'जल बंधन कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान ईरकभट्टी पहुंचने पर अधिकारियों का गोटूल परिसर में पारंपरिक ढंग से ढोल-मांदरी से आत्मीय स्वागत किया गया। आंगनबाड़ी के नन्हे बच्चों ने स्वागत गीत, कविता, गिनती सुनाकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास को देखकर अधिकारी अत्यंत प्रसन्न हुए। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर पेयजल आपूर्ति, जल की गुणवत्ता, नियमित वितरण एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से अब गांव में नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनकी दैनिक समस्याओं में काफी राहत मिली है। ग्रामीणों ने योजना के सुचारू संचालन पर संतोष व्यक्त करते हुए शासन-प्रशासन के प्रति आभार जताया। कलेक्टर नम्रता जैन ने जानकारी दी कि ईरकभट्टी में कुल 55 घर हैं तथा ग्राम को 'हर घर जल ग्राम' घोषित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ग्रामीणों को पेयजल के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय मिशन संचालक के.के. सोन ने ईरकभट्टी की पूसे गोटा के घर पहुंचकर क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का भौतिक निरीक्षण किया तथा जल प्रदाय व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामवासियों एवं हितग्राहियों से चर्चा कर योजना से मिल रहे लाभों और उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी प्राप्त की। कच्चापाल ग्राम पंचायत की सरपंच रजमा नुरेटी ने अधिकारियों को योजना के संचालन एवं संधारण की जानकारी दी। उन्होंने जल गुणवत्ता परीक्षण, नियमित वॉटर टेस्टिंग तथा पेयजल व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। इसके पश्चात निरीक्षण दल ग्राम बेचा पहुंचा, जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित पेयजल व्यवस्था का अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर पेयजल आपूर्ति, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान ग्राम में उत्साहपूर्वक 'जल अर्पण कार्यक्रम' का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय मिशन संचालक के.के. सोन ने ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन का आधार है। पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से जलजनित बीमारियों में कमी आएगी तथा लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। बेचा में 'जल वाहिनी' महिला समूहों द्वारा किए जा रहे जल गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया का भी अधिकारियों ने अवलोकन किया और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं कार्यप्रणाली की सराहना की। ग्रामीण महिलाओं द्वारा तकनीकी रूप से जल परीक्षण किए जाने को उन्होंने आत्मनिर्भरता और जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। ग्राम बेचा में मुरनार सरपंच रजनी नेताम एवं ग्रामीणों द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए पारंपरिक व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों ने मड़िया पेज सहित स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और अबूझमाड़ की समृद्ध संस्कृति, आत्मीयता एवं पारंपरिक खानपान की सराहना की। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मिशन संचालक ओंकेश चंद्रवंशी, मुख्य अभियंता जे.एल. लखेला, अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार शुक्ला, पीएचई कार्यपालन अभियंता एस.के. वर्मा, ओरछा जनपद सीईओ लोकेश चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

25 मई से शुरू होगा नौतपा 2 जून तक रहेगी भीषण गर्मी

कोंडागांव जिला प्रशासन ने दी आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह

कोण्डागांव। प्रदेश में इस वर्ष नौतपा की शुरुआत 25 मई से होगी। ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तभी नौतपा प्रारंभ माना जाता है। यह अवधि 25 मई से 2 जून तक रहेगी। इन 9 दिनों के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे छत्तीसगढ़ समेत पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार, नौतपा जितना अधिक तपता है, मानसून उतना ही बेहतर होता है, जिससे अच्छी बारिश की संभावना बढ़ती है। जिला प्रशासन कोंडागांव एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दौरान लोगों को धूप और लू से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया टीएस बाबा का भव्य स्वागत

भानुप्रतापपुर। प्रदेश के कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री टीएस सिंह देव के भानुप्रतापपुर आगमन पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर एवं आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं एवं जोरदार नारेबाजी के साथ उनका आत्मीय अभिनंदन किया। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव पंकज राज वाधवानी के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यकर्ताओं ने टीएस बाबा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। अपने संबोधन में टीएस बाबा ने कहा कि युवा कांग्रेस संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही जनता की आवाज को मजबूती मिलती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करने एवं संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कृष्णा टेकाम, चेतन मरकाम, सुरेश पंजवानी, विधानसभा अध्यक्ष आकाश यदु, विवेक पांडे, जगजीत नागेश, निलेश कटझरे, प्रसुन पटेल, वेद देवांगन, नवनीत ठाकुर, शुभम ठाकुर, मोहित पटेल, प्रकाश नरेटी, अजय पंजवानी, संदीप सिन्हा, बादल मंडावी, संदीप हिड़ामी, अजय कोराम, प्रमेश शोरी, तामेश, तुलाराम, अश्विनी यादव, योगेश यादव, पुनित, गोलु डड़सेना, गणेश चंद्रोल, आकाश वर्मा, संजय चंद्रोल, खिलेश मंडावी, हरेश गावड़े, तरूण चालकी, नरेश गावड़े, टिकेश नुरेटी, छब्बी कोरेटी, कामेश, सुबरत दास सहित सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव पंकज राज वाधवानी ने कहा कि टीएस बाबा के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस आम जनता के मुददों को मजबूती से उठाते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाएगी।

पेट्रोल–डीजल संकट और महंगाई के खिलाफ कोरर में कांग्रेस का हल्लाबोल

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने किया प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

भानुप्रतापपुर। पेट्रोल-डीजल की किल्लत और लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कोरर में कांग्रेस कमेटी एवं युवा कांग्रेस द्वारा जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। स्थानीय पेट्रोल पंप के सामने आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल-डीजल संकट, महंगाई और आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिला महामंत्री हेमन्त कुमार ध्रुव एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील बबला पाढ़ी, ने कहा कि सरकार एक ओर पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों में ईंधन की भारी कमी देखने को मिल रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार जनता की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जबकि आम आदमी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पेट्रोल-डीजल संकट का समाधान नहीं किया गया और महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से तत्काल ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। धरना-प्रदर्शन में हेमन्त ध्रुव जिला महामंत्री, बबला पाढ़ी अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस भानुप्रतापपुर, गणेश सोनी, रमेश पाण्डेय उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, शोएब अहमद महामंत्री ब्लाक कांग्रेस कमेटी भानुप्रतापपुर, शिवा शुक्ला, सुना राम तेता अध्यक्ष जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर, सौरभ ठाकुर, बृज मड़ावी अध्यक्ष मण्डल कांग्रेस कोरर, सुनहेर गजेंद्र, अशोक गुप्ता, दरिया कोरेटी, बिरझु नेताम, बीरेंद्र कोरेटी,समरेश सोरी, उमाशंकर टेमुन्ना, रामलाल दर्रो, सुरेश राजपूत, पुखराज कोसमा,लीलराम हिड़को, झगरू धनकर,अनुराग शर्मा, आयुष शर्मा, कुणाल टेकाम एव बड़ी संख्या मे कांग्रेस कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

बंदियों के परिजनों को मुलाकाती हेतु उप जेल नारायणपुर में विधिक सहायता हेल्प डेस्क की स्थापना की गई

कोण्डागांव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिंगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय के नेतृत्व में सहायक उप जेल नारायणपुर में बंदियों के परिजनों को विधिक जानकारी एवं प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जेल प्रशासन सहयोग एवं समयवन से उप जेल नारायणपुर के मुलाकाती क्षेत्रों में विधिक सहायता हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जिसका उद्देश्य बंदियों के परिजन/आश्रितों को बंदियों से मुलाकात करने एवं बंदियों की समस्या की जानकारी ली जाकर परिजनों को हेल्प डेस्क के माध्यम से मुलाकात की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत प्रकरण की स्थिति, अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में आवश्यक दस्तावेज, आवेदन संबंधी जानकारी तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में सरल एवं सुगम मार्गदर्शन प्रदान किया जाना है। उक्त विधिक सहायता हेल्प डेस्क में आम आदमी एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी भी दी जा रही है। उक्त हेल्प डेस्क में पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वालेंटियर /अधिकार मित्र नियुक्त है, जो बंदियों एवं उनके परिजनों/ आश्रितों को विधिक सलाह, सहायता संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ मुलाकात प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाना है। जिसका लाभ सीधे बंदियों एवं उनके परिजन/आश्रितों को जेल मुलाकाती क्षेत्र में पहुंच सके।

इंटरनेशनल ठग गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी कॉल कर 30 लाख की ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार

केशकाल-कोंडागांव। फरसगांव पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली और उत्तरप्रदेश से संचालित एक इंटरनेशनल संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीमा लोकपाल बनकर प्रार्थी को झांसे में लिया और लगभग 30 लाख रुपए की ठगी की है। करीब तीन महीने की जांच, तकनीकी विश्लेषण और दिल्ली में लगातार दबिश के बाद पुलिस इस गिरोह तक पहुंचने में कामयाब हुई। इस सम्बंध में जानकारी देते हुए फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने बताया कि कोपरा बाजारपारा निवासी संगम राणा को बीमा लोकपाल परिषद के नाम पर कॉल किया गया। ठगों ने खुद को एजेंट बताकर कहा कि उनकी इंश्योरेंस की लाखों रुपये की राशि फंसी हुई है, जिसे प्रोसेसिंग फीस जमा करने के बाद वापस दिलाया जाएगा। झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग बैंक खातों में करीब 29 लाख 69 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। शिकायत मिलने के बाद फरसगांव पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी विश्लेषण, बैंक खातों की जांच और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए पुलिस को कई अहम सुराग मिले। फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर दिल्ली और उत्तरप्रदेश में लगातार दबिश दी गई। करीब 10 दिनों तक चली कार्रवाई के बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी सिम, बैंक खाते और आधार डिटेल बदलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। रकम खाते में आते ही अलग-अलग एटीएम से पैसे निकाल लिए जाते थे ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंचे। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य आरोपी पहले भी साइबर अपराध के मामलों में जेल जा चुका है और यह नेटवर्क पिछले कई वर्षों से सक्रिय था। फिलहाल पुलिस आरोपियों के अन्य राज्यों में फैले नेटवर्क और बैंक खातों की जांच में जुटी हुई है। इस कार्यवाही में एसडीओपी फरसगांव अभिनव उपाध्याय, निरीक्षक राजकुमार सोरी, उप निरी. शशिभूषण पटेल, प्र.आर. शैलेन्द्र ठाकुर, आर. अजरंग बघेल, रामकुमार ठाकुर, लक्ष्मीनारायण सोरी, महिला आरक्षक सरस्वती यादव सहित साइबर टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का शुभारंभ, दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर

कोण्डागांव। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का शुभारंभ कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना द्वारा किया गया। इस वर्ष उत्सव की थीम सबसे दूर, सबसे पहले निर्धारित की गई है। इस अभियान का उददेश्य दूरस्थ एवं विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में निवासरत हितग्राहियों तक शासन की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित उन्मुखीकरण बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं कार्ययोजना की जानकारी देते हुए विभागीय गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक जनजातीय हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा 18 से 25 मई 2026 तक आयोजित होने वाले सात दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम अंतर्गत प्रचार-प्रसार अभियान, लाभार्थी संतृप्ति एवं स्वास्थ्य शिविर, ट्रांसेक्ट वॉक (ग्राम भ्रमण) तथा आदि सेवा केंद्रों में जनसुनवाई जैसे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम का आयोजन धरती आबा अभियान अंतर्गत चयनित ग्रामों में प्राथमिकता के साथ किया जाए, ताकि सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय नागरिकों तक उत्सव का अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके।

डड़सेना सिन्हा कलार समाज को मिली बड़ी सौगात, नवनिर्मित भवन का अध्यक्ष ने किया लोकार्पण

किरन्दुल। नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह ने सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। डड़सेना सिन्हा (कलार) समाज के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह ने समाज के बहुप्रतीक्षित सामाजिक भवन का विधिवत लोकार्पण किया।वर्षो से समाज के लोग अपने भवन की मांग कर रहे थे, जिसके पूरा होने पर समाज में खुशी का माहौल देखने को मिला।समाज के लोगों ने बताया कि भवन नहीं होने के कारण सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब नए भवन के बनने से समाज को एक स्थायी स्थान मिल गया है, जहां बैठकें एवं विभिन्न कार्यक्रम आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे।नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि सभी समाजों का विकास एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने सामाजिक भवन को समाज की एकता और संगठन का प्रतीक बताया।वार्ड पार्षद बाल सिंह कश्यप ने कहा कि समाज के हित में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी जनसुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

पेंड्रावन में श्रम पंजीयन शिविर का हुआ आयोजन 38 श्रमिकों का हुआ पंजीयन और नवीनीकरण

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप एवं कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिला कोण्डागांव में निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, नवीनीकरण तथा विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ेराजपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत पेण्ड्रावन में मोबाइल पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला कोण्डागांव द्वारा किया गया, जिसमें कुल 36 श्रमिकों का पंजीयन किया गया, वहीं 02 हितग्राहियों का नवीनीकरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सहित श्रमिकों के कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं के लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने श्रमिकों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

कोंडागांव पुलिस ने किया जुआ खेलाने वालों गिरफ्तार

कोंडागांव। जिला कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल के द्वारा अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर थाना प्रभारी कोंडागांव निरीक्षक सौरभ उपाध्याय के नेतृत्व में थाना एवं सायबर सेल की टीम गठित कर लगातार क्षेत्र में पता तलाश किया जा रहा था, कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि सोनावाल के साप्ताहिक बाजार में एवं ग्राम कमेला के वार्षिक मेला में कुछ लोग रुपए पैसे का दाव लगाकर प्रतिबंधित जुआ खुडखुडिया खेला रहे है कि सूचना पर थाना कोण्डागांव एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम को तत्काल रवाना किया गया। जहां ग्राम कमेला वार्षिक मेला स्थल एवं साप्ताहिक बाजार सोनाबाल के कुछ लोग रूपये पैसा का हारजीत का दाव लगाकर खुडखुडिया नामक जुआ खेल रहे थे, जो कि घेराबंदी कर 03 अलग अलग मामलों में 05 व्यक्तियों को रूपये खुडखुडिया जुआ खेलाते पकड़ा गया तथा इनके कब्जे से खुडखुडिया गोटा (पासा), टोकना, खुडखुडी पर्दा नगदी रकम 11475 रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपियों का कृत्य छत्तीसगढ जुआ अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 03 का होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर मौके पर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

खिलोरा में समाधान शिविर बना ग्रामीणों की उम्मीदों का केंद्र, विधायक एवं जिला पंचायत सीईओ ने बांटी आवास की चाबियां

बेमेतरा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखंड बेमेतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत खिलोरा में विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया तथा अपनी समस्याओं और मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होकर विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। शिविर का माहौल पूरी तरह जनसेवा और जनसुनवाई केंद्रित रहा, जहाँ प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद देखने को मिला।

ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही हुआ निराकरण

समाधान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना गया। राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, विद्युत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा सामाजिक कल्याण विभाग सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ आवेदन भी प्राप्त किए गए।शिविर के दौरान अनेक समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया।

जब हितग्राहियों के हाथों में आई अपने सपनों के घर की चाबी

कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण उस समय देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत आवास पूर्ण होने पर हितग्राहियों को उनके नए पक्के मकानों की चाबी और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। वर्षों से कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों के लिए यह पल किसी सपने के साकार होने से कम नहीं था। शिविर में ग्राम खिलोरा की निवासी कलिन्द्री बाई सहित तीन हितग्राहियों को मुख्य अतिथियों के हाथों आवास की चाबी सौंपी गई। अपने पक्के मकान की चाबी हाथ में लेते ही कलिन्द्री बाई की आंखों में खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने शासन, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में जीवन यापन कर सकेगा। हितग्राहियों को आवास की चाबी प्रदान किए जाने के दौरान पूरे शिविर परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने इस पहल को गरीब परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम बताया।

सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना : विधायक

शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों के माध्यम से प्रशासन स्वयं गांवों तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने कहा कि शासन की योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी, जब उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।

अहिवारा के मंगल भवन में जनसमस्या निवारण शिविर संपन्न

दुर्ग। छ.ग. शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत 16 मई को वार्ड क्र. 03 स्थित मंगल भवन में जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया जिसमें शासन के समस्त विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। आयोजित शिविर में वार्ड क्र. 05, 06, 07 एवं 08 के साथ नगर के सभी वार्ड के नागरिकों ने शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए मांग व शिकायत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । साथ में शिविर में अन्य विभागों द्वारा लगाए गए तात्कालिक सुविधा का लाभ लिया गया। आयोजित शिविर में कुल 149 मांग/शिकायत प्राप्त हुई है। शिविर में महिला एवं बाल विकास द्वारा 49 महिला हितग्राहियों का शिविर में ही ई-केवायसी किया गया, 21 हितग्राहियों का आधार अपडेशन और 4 लोगों का तत्काल नया आधार कार्ड बनाया गया। गोद भराई 04 महिलाओं का, आभा आईडी 122, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 53 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाई वितरण किया गया। आयुष हेल्थ परीक्षण और आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण 67 मरीजों को किया गया। परिवहन विभाग द्वारा 22 लोगों का लर्निंग लाइसेंस बनाया गया। साथ ही 4 महिला हितग्राहियों को 20-20 हज़ार का राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का स्वीकृति पत्र, पेंशन स्वीकृति पत्र, 4 हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। शिविर में आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को देखते हुए अहिवारा के सम्माननीय नागरिकों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने हेतु अपील हेतु पांफलेट का भी अनावरण किया गया। आयोजित शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा, अनुविभागीय अधिकारी भिलाई 03 श्री महेश सिंह राजपूत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रवीण सिंह गहलोत , पुलिस विभाग से डीएसपी दानेश्वर साहू, तहसीलदार राधे वर्मा, वार्ड क्र. 02 पार्षद अनुज साहू, वार्ड क्र. 03 पार्षद इंदिरा बंजारे, वार्ड क्र. 05 पार्षद शिवनारायण अग्रवाल, वार्ड क्र. 07 पार्षद कीर्ति राजा शिवाले, वार्ड क्र. 12 पार्षद पुरूषोत्तम वर्मा, वार्ड क्र. 13 पार्षद केशव महिलांग, वार्ड क्र. 15 पार्षद मुकुंद पटेल के साथ समस्त विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी,नगर पालिका के उपअभियंता खिलानंद कुल्हारे एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मौत के साए में चल रहा केज कारोबार : बालोद जिले के जलाशयों में 800 से ज्यादा फिश केज, मजदूरों की सुरक्षा भगवान भरोसे

खरखरा हादसे के बाद खुली पोल, बिना लाइफ जैकेट गहरे पानी में उतारे जा रहे मजदूर, एफआईआर की उठी मांग

बालोद। जिले के डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के खरखरा जलाशय में मजदूर सुखराम सलाम की डूबने से हुई मौत ने जिले में संचालित फिश केज व्यवसाय की भयावह तस्वीर सामने ला दी है। गहरे पानी के बीच सैकड़ों केजों में बड़े स्तर पर मत्स्य पालन का कारोबार तो चल रहा है, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। हादसे के बाद अब जिले के विभिन्न जलाशयों में संचालित केजों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था और विभागीय निगरानी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले के प्रमुख जलाशयों खरखरा, तन्दुला और गोंदली में कुल मिलाकर करीब 800 से अधिक फिश केज संचालित हैं। इनमें बड़ी संख्या में मजदूर रोजाना गहरे पानी के बीच जोखिम उठाकर काम कर रहे हैं। आरोप है कि अधिकांश जगहों पर न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं और न ही आपातकालीन बचाव व्यवस्था। खरखरा जलाशय में मछलियों को दाना डालने गए मजदूर सुखराम सलाम की पानी में डूबने से मौत हो गई थी।

बताया गया कि मजदूर के पास लाइफजैकेट नहीं थी। हादसे के बाद काफी देर तक रेस्क्यू की समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पाई। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर गहरे पानी में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विभाग और संचालक कितने गंभीर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मजदूरों को बिना प्रशिक्षण और बिना सुरक्षा उपकरणों के सीधे केजों में काम पर भेज दिया जाता है। कई मजदूर तैरना तक नहीं जानते, इसके बावजूद उनसे जलाशयों के बीच घंटों काम कराया जाता है। सूत्रों के अनुसार खरखरा जलाशय में कुल 108 केज संचालित हैं। इनमें बंटी हरमुख- 18 केज, पुनम हरमुख- 18 केज, दीपशिखा बनकर- 18 केज, प्रीति मांडवी- 18 केज, अंजलि सलाम- 18 केज, आशीष कुमेटी-एक बड़ा 20×20 केज, जो 18 सामान्य केज के बराबर माना गया है। इन सभी केजों की कुल क्षमता लगभग 1,800 क्यूबिक मीटर प्रति यूनिट बताई जा रही है।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस कार्यक्रम की निकाली गई रैली

दुर्ग। दुर्ग जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा कार्यशाला आयोजित कर कार्यक्रम रैली निकाली गयी, जिसमें एडीज मच्छर के काटने से होने वाले डेंगू की उत्पत्ति के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा एवं बचाव तथा उपचार के बारे मे संपूर्ण जानकारी दिया गया। इस कार्यक्रम में निजी चिकित्सालय एवं पंजीकृत चिकित्सक के समन्वय से समय पर डेंगू रोगीयों की जानकारी प्राप्त कर सम्पूर्ण मुलोपचार, कार्यक्षेत्र की प्रत्येक मितानीन को 3 नारे लेखन हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति तथा शहरी क्षेत्रों में महिला आरोग्य समिति की बैठक आयोजित कर डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समुदाय को जागरुक करने व्यापक प्रचार प्रसार करने निर्देशित किया गया। इस कार्यक्रम में लार्वा स्त्रोत नियंत्रण के तहत नाली की सफाई, कुलर, गमला, टायर, नारियल खोल, टंकी, प्लास्टिक कंटेनर, जल भराव के क्षेत्र एवं झाड़ियों इत्यादि में मच्छर के लार्वा का स्त्रोत पाया जाता है उसे कीटनाशक दवा टेमिफास, मेलाथियान, इत्यादि से विनिष्टीकरण किये जाने हेतु बताया गया यह कार्यक्रम जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आयोजित किया गया एवं जिला अस्पताल दुर्ग में 10 बेड का डेंगू वार्ड पृथक से मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम में डॉ. मनोज दानी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग के मार्गदर्शन में डॉ. संजीव ग्लैड जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी, डॉ. आशिषन मिंज, सिविल सर्जन, डॉ. रश्मि ग्लैड जिला मलेरिया अधिकारी, डॉ.सी.बी.एस. बंजारे जिला नोडल अधिकारी आईडीएसपी दुर्ग के कुशल नेतृत्व मे राष्ट्रीय डेंगू दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मच्छर जनित रोग के बारे में प्रचार-प्रसार बचाव उपचार तथा सभी को मच्छरदानी का उपयोग करने एवं स्त्रोत नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत लार्वा विनिष्टीकरण एवं वयस्क मच्छर का विनिष्टीकरण हेतु बताया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग जिला दुर्ग के समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं नर्सिंग कालेज के प्रभारी व छात्राएं उपस्थित रही व उनके द्वारा डेंगू के रोकथाम हेतु संकल्प लिया गया।

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने जीता, बिलासपुर में आयोजित दक्षिण कोशल कप क्रिकेट प्रतियोगिता

बलौदाबाजार। सरकंडा बिलासपुर के मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के तत्वाधान में आयोजित छ.ग. राज्य स्तरीय रात्रि कालीन क्रिकेट टूर्नामेंट दक्षिण कोशल कप 2026 का खिताब बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस टीम ने जीत लिया है। कल दिनांक 17.05.2026 की रात्रि में खेले गए फाइनल मैच में बलौदाबाजार-भाटापारा की पुलिस टीम ने बिलासपुर पुलिस टीम को शानदार एवं रोमांचक मैच में 05 रन से पराजित करते हुए फाइनल मैच जीतकर विजेता का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट बिलासपुर के सरकंडा मैदान में 27.04.2026 से आयोजित किया गया था, जिसमें 20 जिलों के विभिन्न शासकीय विभागों, प्राइवेट एवं संविदा अधि./कर्मचारियों की कुल 48 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस टीम ने लीग मैंचो में बिलासपुर पुलिस टीम बी, सी, शिक्षा विभाग मस्तूरी, बलरामपुर की टीम तथा सेमी फाइनल मैच में जल संसाधन विभाग बिलासपुर की टीम को परास्त करते हुए शानदार तरीके से फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मैच में टॉस जीत कर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 80 रन का चैलेंजिंग स्कोर खड़ा किया, जिसमें कमलेश मरावी, भूपेन्द्र वर्मा, त्रिलोक चंद्र साहू ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तत्पश्चात बिलासपुर की टीम बैटिंग करने मैदान में आई। इस बीच द्वारिका साहू, प्रीतम पाटले एवं नंद किशोर वर्मा ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पूरी बिलासपुर पुलिस टीम को मैच की अंतिम गेंद तक बांधे रखा, जिसमें अंतिम गेंद पर जीत के लिए 05 रन बिलासपुर टीम नहीं बना सकी और इस प्रकार बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस टीम ने शानदार तरीके से फाइनल मैच जीत कर दक्षिण कोशल कप का खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम के रूप में बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस टीम को 1,00,000 नगद एवं कप से सम्मानित किया गया। संपूर्ण प्रतियोगिता में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करने वाले आरक्षक त्रिलोकचंद साहू को बेस्ट बालर के रूप में रेंजर सायकल और कप तथा फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच आरक्षक द्वारिका साहू को एलसीडी टीव्ही प्रदान किया गया। पुलिस कार्यालय सभा कक्ष बलौदाबाजार में टीम के समस्त खिलाड़ियों से पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा द्वारा भेंटकर उन्हें शुभकामनाएं दिया गया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि पूरे राज्य से आए हुए विभिन्न विभागों की सशक्त टीमों को पराजित कर फाइनल मैच का खिताब अपने नाम करना बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस टीम के सभी खिलाड़ियों के प्रयासों की जमकर सराहना करते हुए एक बार पुनः पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दिया गया।

वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाओं ने की पूजा-अर्चना

अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना,न्यू आदर्श नगर में श्रद्धा और भक्ति के साथ सम्पन्न हुआ व्रत कार्यक्रम,

दुर्ग। वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाओं ने आज न्यू आदर्श नगर, जोन-3 मार्ग क्रमांक 8 में शुक्रवार को सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने वट (बरगद) वृक्ष की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु एवं परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

पूजा के दौरान महिलाओं ने बरगद के पेड़ पर जल अर्पित किया तथा रोली, अक्षत, फूल एवं पूजा सामग्री चढ़ाकर परंपरागत रीति-रिवाजों का पालन किया। इसके पश्चात महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर तने पर कच्चा सूत लपेटते हुए पूजा सम्पन्न की। पूरे आयोजन में श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। इस अवसर पर महिलाओं ने माता सावित्री एवं सत्यवान की कथा का श्रवण एवं वाचन किया। कथा के माध्यम से बताया गया कि वट सावित्री व्रत माता सावित्री के अपने पति सत्यवान के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है, जिन्होंने अपने तप, साहस और दृढ़ संकल्प से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए थे।

शिक्षक ललित बिजौरा को मिला राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान

पाटन ब्लॉक सहित दुर्ग जिले को किया गौरवान्वित

अमलेश्वर। राजधानी रायपुर में शिक्षा जगत का एक बड़ा और गौरवशाली समागम संपन्न हुआ, नवाचारी गतिविधियां समूह भारत की छत्तीसगढ़ टीम द्वारा राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान सह संप्रवाह 2025-26 का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रो. जे. एन. पांडेय विद्यालय रायपुर में किया गया । इस समारोह में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से चयनित 160 उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके नवाचारी गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया ।जिसमें दुर्ग जिले के 3 शिक्षकों को उनके नवाचारी गतिविधियों एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मगरघटा संकुल केंद्र परसदा विकासखंड पाटन जिला दुर्ग में पदस्थ शिक्षक ललित कुमार बिजौरा को उनके उल्लेखनीय एवं नवाचारी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय नवाचारी शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया । इस आयोजन का संचालन नवाचारी गतिविधियां समूह भारत की छत्तीसगढ़ टीम द्वारा किया गया , जो देशभर के शिक्षकों को नवाचार के माध्यम से जोड़ने वाला एक प्रमुख स्व प्रेरित मंच है । इस कार्यक्रम में दुर्ग जिले के 3 नवाचारी शिक्षकों ललित कुमार बिजौरा पाटन, मंजू पाठक दुर्ग, नीलम विकास सुखदेवे धमधा का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत के कई वरिष्ठ अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही।

इनमें उप सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर डॉ. बी.रघु, उप संचालक समग्र शिक्षा रायपुर ए.के.सारस्वत, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर हिमांशु भारती, डीएमसी रायपुर अरुण कुमार शर्मा, प्राचार्य सेजस हिंदी माध्यम रायपुर सुचिता पाण्डेय शामिल रहे। सभी अतिथियों ने शिक्षकों के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के मंच शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने एवं सीखने सीखाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

शासकीय भूमि पर 28 वर्षों से किए गए अतिक्रमण को किया कब्जा मुक्त

सरपंच रमाकांत साहू ने किया धारा 56 का प्रभावी उपयोग

पाटन। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत ग्राम पंचायत आगेसरा के युवा सरपंच रमाकांत साहू द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 56 का प्रभावी उपयोग करते हुए खसरा नंबर 519 रकबा लगभग 1 एकड़ में फकीरा राम निषाद द्वारा लगभग 28 वर्षो से सरकारी घास भूमि पर खेत बनाकर किए गए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत आगेसरा के उप सरपंच, सचिव, कोटवार एवं पंच गण एक मत होकर ग्राम आगेसरा के समस्त नागरिकों से विचार विमर्श कर घटना की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन तहसीलदार पाटन, जामगांव राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से विगत 6 माह तक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए यह कार्यवाही किया गया, कब्जा मुक्त होने के उपरांत संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी से अवगत कराया गया। सरकारी जमीन पर हुए इस कब्ज को ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों एवं गांव के समस्त नागरिकों के सहयोग से इस भूमि को कब्जा मुक्त किया गया।

शाला खर्री टोला के प्राथमिक परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा

दल्लीराजहरा। शासकीय प्राथमिक शाला खर्री टोला के प्राथमिक परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। कक्षा में तीन छात्र-छात्राएं की दर्ज संख्या थी जहां सभी ने इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। शाला में छायांक कुमार नेताम 90.50 प्रतिशत अंक अर्जित का प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रंजीत ने 88% के साथ द्वितीय एवं दीपांजलि ने 77% अंक के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। स्कूल के छात्र छायांक कुमार नेताम का नवोदय में चयन हुआ है। स्कूल प्रबंधन समिति एवं शाला परिवार की ओर से स्कूल में उत्कृष्ट परिणाम लाने तथा नवोदय में चयन होने पर उन्हें हार्दिक बधाई दिया गया है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है।

1 से 60 वार्डों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

दुर्ग। नगर पालिक निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल द्वारा शहर के एक से लेकर 60 वार्डों तक नागरिक सुविधाओं की सतत निगरानी एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सचिव महोदया द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में यह व्यवस्था लागू की गई है। नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपने-अपने वार्डों में सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, विद्युत संबंधी समस्याओं एवं अन्य जनसुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995